

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> युवा केवल नौकरी मांगने ...



हार के बाद कर रही संवैधानिक संस्थाओं का अपमान

स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर करारा हमला

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी चुनावी हार पर विचार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है और भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी ने वोटर लिस्ट में बदलाव और उसे अपडेट करने के बारे में विपक्ष की हालिया टिप्पणियों की निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार का जिक्र किया कि लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध तो होता है, लेकिन अहम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले नहीं होने चाहिए। ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार कहा है- उनकी आलोचना करें, उन पर हमला करें, लेकिन इस हमले को संवैधानिक संस्थाओं और भारत के लोकतंत्र पर हमले में न बदलने दें। हालांकि, कांग्रेस



नेतृत्व भारत के संवैधानिक ढांचे को तहस-नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वोटर लिस्ट अपडेट में 13.3 करोड़ एंट्रीज के बारे में कांग्रेस के दावों पर बात करते हुए, उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने बुध लेवल अधिकारियों द्वारा डुप्लीकेट और मृत वोटरों को हटाने के लिए किए गए घर-घर जाकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर एक अधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया था।

ईरानी ने वोटर लिस्ट को ठीक करने के विरोध में विपक्ष के इरादों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर वोटर लिस्ट में

डुप्लीकेट नाम या मृत लोगों के नाम हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है कि मृत लोगों के नाम वापस जोड़े जाएं? कांग्रेस पार्टी क्यों चाहती है कि डुप्लीकेट एंट्रीज बनी रहें? उन्होंने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए, जहाँ गैर-बीजेपी सरकारें सत्ता में हैं। उन्होंने पूछा कि क्या पार्टी उन इलाकों में भी चुनाव आयोग के लिए वही पैमाने अपनाती है।

कांग्रेस द्वारा आज़ादी से पहले के लाहौर अधिवेशन का जिक्र किए जाने को खारिज करते हुए, ईरानी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत का जिक्र किया और औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए इसके गठन में ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम की भूमिका को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाई गई कांग्रेस पार्टी आज भारत के चुनाव आयोग पर हमला कर रही है।

कांग्रेस करेगी सड़क से संसद तक विरोध

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि देश में ईवीएम और मतदाता सूची के जरिए चुनावों में मैच फिक्सिंग की जा रही है। दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई करीब ढाई घंटे की सीडब्ल्यूसी बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को सड़कों से लेकर संसद तक विरोध और प्रतिरोध के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े कई खुलासे अब सामने आ रहे हैं और ऐसा कांग्रेस की वजह से संभव हुआ है।

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी के मुद्दे को मजबूती से उठाती रही है। उन्होंने हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में चुनावों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी के मुताबिक, शुरुआत में कई लोग कांग्रेस के दावों को लेकर आशंकित थे। राहुल गांधी ने कहा कि अब यह मुद्दा मीडिया और संपादकीय लेखों में भी चर्चा का विषय बन रहा है। उनके मुताबिक, पिछले दो वर्षों में माहौल बदला है और इसके पीछे कांग्रेस की ओर से तथ्यों पर आधारित प्रस्तुतियाँ प्रमुख कारण हैं। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि चुनावों में दो तरह की मैच फिक्सिंग हो रही है। एक ईवीएम से जुड़ी है और दूसरी मतदाता सूचियों में जानबूझकर किए जा रहे बदलाव से। उन्होंने कहा, इसलिए मैच फिक्सिंग के दो रूप हैं-ईवीएम मैच फिक्सिंग और वोटर लिस्ट मैच फिक्सिंग, दोनों हो रहे हैं।

एशियन गेम्स : नीरू का गोल्ड भारतको 4×400 रिले में सोना

आइची नागोया। एशियन गेम्स 2026 में 29 सितंबर को भारत के लिए कई बड़ी उपलब्धियां देखने को मिलीं। शूटिंग में नीरू ढांडा ने महिला ट्रेप की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले नीरू, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की तिकड़ी ने महिला ट्रेप टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में भारत ने महिला 4×400 मीटर रिले में स्वर्ण के अलावा गुलवीर सिंह के जरिए 5000 मीटर में कांस्य हासिल किया। पूजा सिंह ने महिला ऊंची कूद और मिश्रित 4×100 मीटर रिले टीम ने भी कांस्य पदक जीता। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा और अंकुश पंचाल फाइनल में पहुंच गए,



जबकि नरेंद्र को कांस्य पदक मिला। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने भी कतर को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रेप की व्यक्तिगत स्पर्धा में 30 में से 28 निशाने लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीन की यूनॉंग सुन ने 26 के स्कोर के साथ रजत पदक जीता। नीरू ने इस प्रदर्शन के साथ एशियन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे पहले महिला ट्रेप के

व्यक्तिगत फाइनल में एशियन रिकॉर्ड 24 का था। नीरू का स्वर्ण इस स्पर्धा में भारत का पहला एशियाई खेल पदक भी है। महिला ट्रेप 1990 से एशियन गेम्स का हिस्सा है, लेकिन भारत को इस इवेंट में अब तक कोई पदक नहीं मिला था। नीरू ने 36 साल के इंतजार को खत्म करते हुए सीधे स्वर्ण पदक दिलाया। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का पांचवां स्वर्ण था।

सीजेपी को नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी कर लेना चाहिए

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मंगलवार को कांिकरोच जनता पार्टी पर तर्ज कसते हुए युवाओं के नेतृत्व वाले इस समूह का नाम बदलने का सुझाव दिया। अठावले ने कहा कि सीजेपी को अपना नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी कर लेना चाहिए। यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के बीच आई है, क्योंकि वे भारत निर्वाचन आयोग के भीतर कथित असहमति को लेकर एक बड़े विवाद में फिरे हुए हैं।

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सीईसी के इस्तीफे की मांग करते हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। इससे पहले जुलाई में, नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों को लेकर



सीईसी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। मंगलवार को सीजेसी पर निशाना साधते हुए अठावले ने कहा कि सीजेपी सिर्फ इस्तीफे की मांग करती रहती है। उन्हें इसका नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी कर देना चाहिए।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि दिपके हाल ही में राजनीति में आए हैं, जबकि वे खुद लंबे समय से दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

पीएनबी घोटाला : नीरव मोदी का करीबी संदीप मिस्त्री गिरफ्तार

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के सहयोगी संदीप मिस्त्री को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पण के बाद मंगलवार को मुंबई में मिस्त्री को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। मिस्त्री को सोमवार को यूएई से भारत लाया गया था। मंगलवार को सीबीआई ने उसे गिरफ्तार करने के बाद विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया। एजेंसी ने उसकी हिरासत की मांग नहीं की। इसके बाद अदालत ने मिस्त्री को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह गिरफ्तारी नवंबर 2025 में विशेष अदालत की ओर से जारी गैर-जमानती वारंट के अनुपालन में की गई है। संदीप मिस्त्री नीरव मोदी की हांगकांग स्थित कंपनी फैंसी क्रिएशंस लिमिटेड में निदेशक रह चुका है। सीबीआई का आरोप है कि मिस्त्री ने नीरव मोदी और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई।



मुंबई में नहीं उतर सका विमान सवा घंटे तक लैंडिंग की कोशिश

नई दिल्ली। दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6ई 864 खराब मौसम और टर्बुलेंस के कारण मुंबई में निर्धारित समय पर लैंड नहीं कर सकी। विमान को शाम करीब 5:45 बजे मुंबई पहुंचना था, लेकिन मौसम की स्थिति खराब होने के चलते लैंडिंग में देरी हुई। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को मुंबई आने वाली 11 उड़ानों को खराब मौसम के कारण आस-पास के अलग-अलग हवाई अड्डों पर भेजना पड़ा है। पायलट ने मुंबई एयरपोर्ट पर विमान उतारने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम और तेज टर्बुलेंस के कारण लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। इसके बाद विमान करीब सवा घंटे तक हवा में रहा। स्थिति को देखते हुए फ्लाइट को मुंबई के बजाय सूरत एयरपोर्ट डायवर्ट किया गया, जहां विमान को उतारा गया। हालांकि, इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट पर पीएनआर चेक करने पर फ्लाइट की स्थिति अलग दिखाई दे रही है। वेबसाइट के मुताबिक, 6 ई 864 करीब 1 घंटे 16 मिनट की देरी के साथ शाम 7:01 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है।



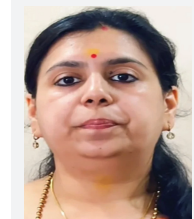
संजू की स्वर्णिम जीत पर उप मुख्यमंत्री साव ने थपथपाई पीठ

रायपुर। एशियन गेम्स-2026 में महिला कबड्डी में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी ने रायपुर लौटने के बाद उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरुण साव से मुलाकात की। श्री साव ने अपने नवा रायपुर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान संजू देवी की उपलब्धि पर उनका अभिनंदन कर हौसला बढ़ाया। उन्होंने संजू की माता श्रीमती अमरीका बाई और पिता श्री रामजी का भी अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने संजू देवी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने भारत के साथ छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ लोगों को भी गौरवान्वित किया है। उन्होंने संजू से एशियन गेम्स के अनुभव और उनकी टीम के स्वर्ण पदक तक के अजेय सफर की जानकारी ली। श्री साव ने उनसे प्रतियोगिता के दौरान मिले अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की।



पूर्व आईएएस दिव्या मित्तल का सियासी पारी का ऐलान

पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने आज सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान कर उत्तर प्रदेश की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। मित्तल ने साफ किया कि वह किसी स्थापित राजनीतिक दल के सहारे नहीं, बल्कि स्वतंत्र मंच के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत इसी प्रदेश से होगी। एक वीडियो संदेश में दिव्या मित्तल ने बताया कि प्रशासनिक सेवा के दौरान जनता के बीच काम करते हुए उन्हें कई ऐसी हकीकतों का सामना करना पड़ा, जिसने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। उनका कहना था कि सरकारी मंजूरी, धन और नियम-कायदे मौजूद होने के बावजूद आम लोगों की अनेक समस्याएं वर्षों तक जड़ की तस पड़ी रहती हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों की आवाज सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती और जिनको आवाज पहुंचती भी है।



नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के दिसंबर 2026 में होने वाले आम और उप चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए 29 सितंबर 2026 को पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि नगरपालिका आम निर्वाचन के लिए कुल 417 पदों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इनमें 4 नगरपालिका निगम भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बीरगांव के महापौर, 13 अध्यक्ष और 400 पार्षद पद शामिल हैं। वहीं उप निर्वाचन के लिए 1 अध्यक्ष और 6 पार्षद पदों के लिए भी निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए कुल 814 पदों के लिए निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। इनमें जनपद पंचायत सदस्य के 1, सरपंच के 92 तथा पंच के 721 पद शामिल हैं।



स्वायत्त व मजबूत सांविधानिक संस्थाएं बनाने की जरूरत, यही लोकतंत्र के लिए शुभ

नई दिल्ली। चुनाव आयुक्तों की साझा मीटिंग और स्पष्टीकरण के बाद सांविधानिक बिंदुओं पर विवाद खत्म होना चाहिए। पुरानी घटनाओं से समझें, तो अदालत और मीडिया में बहस जारी रहेगी। चुनाव आयोग में विरोधाभास और असहमति का लंबा इतिहास रहा है। 1989 में मुख्य चुनाव आयुक्त आरवीएस पेरी शास्त्री ने दो नए आयुक्तों की नियुक्ति का विरोध किया। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेन ने संसद से पारित कानून को चुनौती देते हुए अन्य दो आयुक्तों को काम करने की इजाजत ही नहीं दी। शेपन के विरोध को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों चुनाव आयुक्तों को बराबरी का

सांविधानिक दर्जा देने का फैसला दिया। लेकिन, तीन सदस्यीय आयोग में आंतरिक विरोधाभासों का सिलसिला जारी रहा। 2009 में मुख्य चुनाव आयुक्त गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला के खिलाफ राजनीतिक जुड़ाव की शिकायत की थी, लेकिन हटाने के बजाय चावला को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त कर दिया गया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हेतु स्वतंत्र कॉलेजियम बनाने के लिए 2015 में याचिका दायर हुई थी। उसके आठ साल बाद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नया कानून बनाने का आदेश दिया। संसद से बने नए कानून में तीन सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष

और केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री के बजाय समिति में सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल करने के लिए एक नई याचिका दायर हुई थी। उस पर तीन साल बाद दो जजों की पीठ का खंडित फैसला आया। चुनाव आयोग के आंतरिक विवादों की मीडिया रिपोर्टिंग के बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सनसनी ज्यादा बढ़ गई। पर, उच्चतम न्यायालय के फैसले की खामियों का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। पुराने मामले में पांच जजों की संविधान पीठ का फैसला था, तो नई याचिका के लिए दो जजों की बेंच क्यों बनाई गई? दूसरे न्यायाधीश के फैसले के अनुसार, संविधान पीठ में सुनवाई



होनी चाहिए, तो याचिका को तीन साल तक लंबित क्यों रखा गया? जज के बेटे चुनाव आयोग के वकील हैं, तो हितों के विरोधाभास के आधार पर उन्होंने सुनवाई में शामिल होने से इन्कार क्यों नहीं किया? मुख्य चुनाव आयुक्त की

आईएएस बेटे से जुड़े एक मामले की सुनवाई उन्हीं जज की पीठ के सामने आने के बाद न्यायिक व्यवस्था भी आलोचना के घेरे में आ गई। पुरानी घटनाओं से सबक लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमियों को चुनाव आयोग से जोड़कर सोशल मीडिया पर अभियान चलाने से सांविधानिक संस्थाओं का भरोसा डगमगाता है। सिर्फ भारत के नागरिकों के नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए सिलसिलेवार तरीके से राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। बिहार मामले में

सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को मंजूरी दी थी। तब चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि बिहार के अनुभवों से सबक लेकर एसआईआर की प्रक्रिया सरल और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। चुनाव आयुक्त संधू ने भी पिछले साल पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमियों को चुनाव आयोग से जोड़कर सोशल मीडिया पर अभियान चलाने से सांविधानिक संस्थाओं का भरोसा डगमगाता है। बाहर होने के कारण बढ़ रहे विवाद और आक्रोश का समाधान भी जरूरी है। 99 फीसदी से अधिक नोटिस नाम, उम्र और मैपिंग में गड़बड़ी के कारण जारी हुए हैं। इससे साफ है कि जो लोग घुसपैठिये

नहीं हैं, उन्हें तकनीकी कारणों से बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंगलूरू में पासपोर्ट थारकों से भी नागरिकता का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जिसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली में हल्ला मचने के बाद वीआईपी लोगों को नोटिस देने के बजाय फील्ड विजिट के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने की पहल हुई है। इसी तरह से पासपोर्ट थारक, सरकारी अधिकारी, पीएसयू कर्मों, वकील, डॉक्टर, सीए, जज, विधायक, सांसद और सामान्य कर्दाताओं को एसआईआर की कठोर प्रक्रिया से दूर रखकर वोटर लिस्ट में उनका नाम बरकरार रखने की जरूरत है।

मंच पर सितारे चमके, पर्दे के पीछे भी दमके ‘चक्रधर’ के शिल्पकार

रायगढ़। दस दिनों तक रायगढ़ की धरती पर कला, संगीत और संस्कृति का ऐसा संगम सजा कि 41वें चक्रधर समारोह का समान भी अपने पीछे यादों की एक लंबी इबारत छोड़ गया। अंतिम शाम स्वर कोकिला कविता कृष्णमूर्ति के सुरीले गीतों ने जब वातावरण को सुरमयी किया तो पूरा समारोह मानो अपनी सफलता के चरम पर पहुंच गया। हालांकि इस भव्य आयोजन की चमक केवल मंच पर प्रस्तुति देने वाले कलाकारों तक सीमित नहीं



रही। इसके पीछे आयोजन को आकार देने वाले उन चेहरों की भी उतनी ही अहम भूमिका रही,

जिन्होंने दस दिनों तक इसकी हर कड़ी को मजबूती से संभाले रखा। आयोजन समिति के

अध्यक्ष एवं कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की सुनियोजित

तैयारियां मुख्य उद्घोषक प्रो. अंबिका वर्मा की दमदार और प्रभावशाली आवाज,नगर विधायक ओपी चौधरी की दूरदर्शी पहल,राजपरिवार के सदस्य एवं राज्यसभा सांसद कुमार देवेंद्र प्रताप सिंह की सक्रिय सहभागिता और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में आईपीएस मयंक मिश्रा एवं टीम की मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था ने इस विराट आयोजन को सफलता की मुकम्मल तस्वीर दी। खास तौर पर बस्तर में नक्सल हिंसा का रास्ता छोड़कर

मुख्यधारा में लौटे आदिवासियों को चक्रधर समारोह के प्रतिष्ठित मंच तक पहुंचाने की पहल ने समारोह को सांस्कृतिक आयोजन से आगे बढ़ाकर बदलते छत्तीसगढ़ की एक संवेदनशील तस्वीर भी बना दिया। देशभर से आए कलाकार जब रायगढ़ की मेहमाननवाजी, आयोजन की भव्यता और व्यवस्थाओं की प्रशंसा कर लौटे, तो उनकी प्रशंसा में मंच के साथ-साथ पर्दे के पीछे खड़े इन सभी ‘शिल्पकारों’ की मेहनत भी साफ दिखाई दी।

नान के मैनेजर को एसीबी ने किया ट्रैप, कमीशन लेते रंगे हाथों पकड़ा

बलरामपुर। बलरामपुर जिला मुख्यालय में मंगलवार को कलेक्टोरेट स्थित नागरिक आपूर्ति निगम कार्यालय में, छ्क की टीम ने दबिशा देकर मैनेजर को रंगे हाथों अरेस्ट किया।मैनेजर पर बिल के भुगतान के एवज में रिश्तत मांगने की शिकायत एसीबी की मिली थी।



नागरिक आपूर्ति निगम दफ्तर में हुई कार्रवाई

अंबिकापुर की शिवराज सिंह फर्म ने नागरिक आपूर्ति निगम बलरामपुर में ट्रांसपोर्टिंग का काम किया था। इस कार्य का लगभग 11 लाख 30 हजार रुपये का बिल भुगतान विभाग की ओर से किया जा चुका था। लेकिन भुगतान देने के बदले मैनेजर विद्यासागर गोपाल ने फर्म संचालक से दो फीसदी कमीशन मांगा था। यह कमीशन करीब 22 हजार रुपए बताई जा रही है। सत्यापन कराया। सत्यापन में शिकायत सही

पाए जाने के बाद एसीबी ने मंगलवार को बलरामपुर कलेक्टोरेट पहुंचकर आरोपी प्रबंधक को ट्रैप किया। मैनेजर ने जैसे ही रिश्तत की रकम ली वैसे ही एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। अब एसीबी की टीम आरोपी मैनेजर के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर रही है। आरोपी प्रबंधक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा फिलहाल एंटी करप्शन की टीम जांच और कार्यवाही में जुट गई है।

एसीबी ने वाड्फनगर तहसील क्षेत्र के पंडरी गांव में इससे पहले एक्शन लिया था। यहां तैनात हलका पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 13 हजार की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया था। पटवारी का नाम मोहन सिंह था। मोहन सिंह पर एक किसान से जमीन बंटवारे के एवज में रिश्तत मांगने का आरोप था।आरोप की जांच में सत्यता मिलने पर एसीबी ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथों अरेस्ट किया था।

जनदर्शन में कलेक्टर ने सुनीं आमजन की समस्याएं, त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

एमसीबी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याएं और मांगें सुनीं। इस दौरान आवास, भूमि, पेंशन, वनाधिकार पट्टा, आंगनबाड़ी केंद्र, बीमा क्लेम और मजदूरी भुगतान सहित विभिन्न मामलों के आवेदन सामने आए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनदर्शन में नागपुर निवासी धरमसाय को शासकीय भूमि का पट्टा दिए जाने के लिए आवेदन किया। वहीं नागपुर निवासी धरसाय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास की वर्ष 2025 की सूची में नाम आने के बावजूद अब तक आवास निर्माण के लिए राशि नहीं मिली है। नागपुर की संध्या देवी ने विधवा पेंशन शुरू कराने की मांग रखी।



गिरवानी निवासी आनंद प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत कर जांच की मांग की। बरहोरी की मीना देवी ने भूमि संबंधी प्रकरण को लेकर आवेदन सौंपा।

कछौड़ निवासी विजेन्द्र सिंह मसराम ने सोको बहरा में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग रखी। चरवाही निवासी गुलाब ने वनाधिकार पट्टे में खसरा नंबर सुधारने के लिए आवेदन किया, जबकि दूगपाल सिंह ने फर्जी पट्टा वितरण की शिकायत

करते हुए जांच की मांग की। ग्राम कोड़ा के हितग्राहियों ने आवास प्लस सूची में दर्ज दावा-आपत्तियों का 15 दिन के भीतर निराकरण नहीं होने की समस्या से कलेक्टर को अवगत कराया। जनदर्शन में योगिता चवड़ा ने लंबित बिल के भुगतान, उमरवाह के

मजदूरों ने चेकडेम निर्माण कार्य की लंबित मजदूरी के भुगतान की मांग रखी। रामवती ने सीपीएस राशि के भुगतान के लिए आवेदन दिया। मनेन्द्रगढ़ निवासी गृधिया केवट ने समूह को कार्य की आवश्यकता की जानकारी प्रेषित किए जाने के संबंध में अपनी समस्या रखी।

लंबित प्रकरणों में अनावश्यक देरी न हो- कलेक्टर

कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने प्रत्येक आवेदक की समस्या सुनने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनदर्शन में मिले आवेदनों का प्राथमिकता से परीक्षण किया जाए और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने लंबित मामलों के निराकरण में अनावश्यक विलंब नहीं करने और आमजन से जुड़े प्रकरणों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

नक्सली डंप से बरामद लाखों की रकम के गबन का आरोप

कांकेर एसपी ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई

कांकेर। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान इस साल मार्च और अप्रैल के महीने में 2 बड़े नक्सली डंप पुलिस ने सर्चिंग के दौरान बरामद किए। बरामद दोनों डंप मुरारगांव के जंगलों से मिले थे। कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने कहा, %०सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों की टीम टोंडेमरका और मरमाकोनारी के जंगलों में गई थी। सर्चिंग के दौरान दोनों जगहों से जवानों को माओवादियों द्वारा छिपाए गए 2 नक्सली डंप बरामद हुए। पहले डंप से पुलिस को 15 लाख की नकदी मिली, जबकि दूसरे डंप से 5 लाख की नकदी बरामद की गई।%०



सरकारी प्रक्रिया के तहत डंप सामान की सूची बनाई जाती है, फिर पंचनामा कर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे सरकारी मालखाने में जमा करा दिया जाता है। लेकिन आरोप है कि 2 नक्सली डंप से बरामद 20 लाख की रकम को कानूनी प्रक्रिया के तहत

जमा नहीं किया गया, बल्कि उसका गबन कर लिया गया। इस गबन का आरोप उस वक्त के 2 तत्कालीन डीएसपी पर है, हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। जिन 2 डीएसपी पर गबन का आरोप है, वो फिलहाल दूसरे जिलों में तैनात हैं।

पुलिस अधीक्षक निखिल कुमार राखेचा ने कहा, जो रकम मिलने और गबन किए जाने की बात सामने आई है, उसकी जांच की जाएगी और जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसे साझा किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि दोनों मामलों की प्रार्थमिक जांच पूरी कर रिपोर्ट आगस्त में उच्च अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। अब आगे के निर्देश का इंतजार है।

सौंगा से नाले में बही छात्रा का शव बरामद

धमतरी। मगरलोड में तेज बारिश के दौरान नाले में बही 14 साल की छात्रा तराना निषाद का शव 3 दिन बाद बरामद किया गया।आपको बता दें कि बच्ची की तलाश में 26 सितंबर से पुलिस,एसडीआरएफ और नगर सैनिक गोताखोरों की टीम लगी थी। छात्रा का शव महानदी के सौंगा क्षेत्र से बरामद किया गया। मगरलोड थाना क्षेत्र के मेघा गांव की रहने वाली 14 वर्षीय तराना निषाद 26 सितंबर को मेघा स्थित पेट्रोल पंप के पास गई थी। इसी दौरान वह नाले के पास खेल रही थी। उस समय जिले में तेज बारिश हो रही थी और नदी-नाले उफान पर थे। खेलते समय अचानक तराना नाले में गिर गई और पानी के तेज बहाव के साथ बह गई।



हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों और परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन बच्ची को खोजने के लिए मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मगरलोड पुलिस ने तत्काल सर्चिंग अभियान शुरू किया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम और नगर सैनिक गोताखोरों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया। 26 सितंबर को तराना निषाद पेट्रोल पंप के पास नाले में गिर

गई थी। तेज बहाव के कारण वह पानी में बह गई थी। घटना के बाद से पुलिस, एसडीआरएफ और नगर सैनिक गोताखोरों की टीम लगातार उसकी तलाश कर रही थी। मंगलवार को तराना का शव महानदी के सौंगा में बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कई घंटों तक नाले और आसपास के इलाकों में सर्चिंग की गई। नदी के तेज बहाव और लगातार बारिश के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पानी का बहाव तेज होने के कारण बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसके बावजूद पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार अलग-अलग संभावित स्थानों पर तलाश करती रही।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार	राजनीतिक पार्टी में बड़ा पद दिलाने का झांसा, महिला गिरफ्तार	भिलाई वासियों की जीत सरकार और संगठन मेरे साथ: विधायक सेन	बदमाशों ने युवक को सड़क पर पटक-पटककर पीटा	नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी के मामले में नया मोड़	छात्रावास में चोरी का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
	बिलासपुर। राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने और पार्टी फंड के नाम पर एक निजी सलाहकार से 82 लाख 63 हजार 194 रुपए की ठगी करने के मामले में सरकंडा पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरकंडा पुलिस के मुताबिक, सरकंडा क्षेत्र के श्री विहार निवासी चेतन आनंद दुबे की वर्ष 2025 में फेसबुक के माध्यम से निखत परवोन शाहरी उर्फ निकहत शाहरी उर्फ निक्की से पहचान हुई थी। आरोपी महिला ने खुद को राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताते हुए बड़े नेताओं से करीबी संपर्क होने का दावा किया। जमीन विवाद सुलझाने के नाम पर उसने प्रार्थी का विश्वास हासिल किया। इसके बाद आरोपी ने प्रार्थी को राजनीति में रुचि का फायदा उठाते हुए राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा पद दिलाने और पार्टी में ज्वाइनिंग कराने का झांसा दिया। पुलिस के अनुसार, पार्टी फंड और कागजी प्रक्रिया के नाम पर प्रार्थी और उसके परिचितों सतीश अग्रहरी, अंकित पाण्डेय और डॉ। गायत्री गुप्ता के खातों से रकम ली गई। इसके अलावा नकद राशि भी ली गई। कुल मिलाकर 82,63,194 रुपए लिए गए।	दुर्ग। बीएसपी लोहा चोरी केस की जांच अब सीबीआई करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। गृह विभाग ने 25 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। उसके बाद से इस केस में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। भिलाई स्टील प्लांट में लोहा स्ट्रैप चोरी के संबंध में पुरानी भिलाई थाने में अपराध क्रमांक 277/2026 दर्ज किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। इनमें धारा 303(2), 317(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 111, 112, 61(2)(क) और 3(5) शामिल हैं। मामले की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत अपनी सहमति प्रदान की है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है, ताकि पुरानी भिलाई थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 277/2026 की जांच की जा सके।	कोरबा। मानिकपुर चौकी क्षेत्र के कृष्णा नगर बस्ती में देर रात पान ठेले पर सिगरेट देने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मारपीट की पूरी वारदात पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार राहुल शांडिल्य अपने साथी दक्ष निराला के साथ बाइक से किसी काम से गए थे। घर लौटते समय दोनों कृष्णा नगर बस्ती में देर रात तक खुले पान ठेले पर रुके और सामान लिया। इसी दौरान तरुण साहू, देवेंद्र सिंह और लाला नामक युवक भी वहां पहुंचे और दुकानदार से सिगरेट मांगी। सीसीटीवी फुटेज में तीन युवक एक युवक को सड़क पर पटक-पटककर मारते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में एक युवक पर पत्थर से सिर पर हमला करने की कोशिश भी नजर आ रही है। घटना के बाद युवक की हालत गंभीर बताई गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मानिकपुर सहायता केंद्र अंतर्गत कृष्णा नगर में सिगरेट को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था।	सूरजपुर। नौकरी लगाने के नाम पर 16 लाख रुपये की ठगी के आरोप से जुड़ा मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। रिटायर्ड स्क्वैडरु कर्मी की शिकायत के बाद सरपंच प्रतिनिधि बृजलाल लकड़ा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपों को झूठ बताते हुए इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। वहीं सरपंच संघ ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल, बीते 25 सितंबर को तेजपुर निवासी रिटायर्ड स्क्वैडरु कर्मी बिरंजन ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के ही बृजलाल लकड़ा और संतोषी लकड़ा ने उनके परिजनों की नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 16 लाख रुपये की ठगी की है। शिकायत के बाद मामले में अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। बृजलाल लकड़ा के साथ 8-10 सरपंच एसपी कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर रिटायर्ड स्क्वैडरु कर्मी की शिकायत को झूठ और राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। इस दौरान बृजलाल लकड़ा ने कहा कि वह तेजपुर गांव का सरपंच प्रतिनिधि है और उसके पास फोर व्हीलर गाड़ी है।	कोरिया। थाना पटना पुलिस ने प्रो-मैट्रिक छात्रावास में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई सैमसंग एलईडी टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर, सोने की चेन, चांदी की पायल और कान की बाली समेत करीब 1 लाख 80 हजार रुपये का सामान बरामद कर जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, 22 अप्रैल 2026 को प्रो-मैट्रिक छात्रावास पटना की अधीक्षिका के आवास का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर, सोने-चांदी के आभूषण और 50 हजार रुपये नकद समेत करीब 2 लाख 30 हजार 600 रुपये की संपत्ति चोरी कर ली थी। मामले में थाना पटना में अपराध क्रमांक 115/2026 के तहत धारा 331(4), 300(1), 3(8) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों की तलाश के लिए मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। मुखबिर से मिली सूचना और पुलिस को तस्दीक के आधार पर सरना पारा निवासी महबूब रजा उर्फ बाबू (19) और सौरभ गुप्ता उर्फ राजा गुप्ता (24) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

काली-मिर्च गिलोय सिंदूरी के पौधे मिले, सैकड़ों बच्चों व किसानों के चेहरे खिले

कोंडागांव। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मयूर डोंगर में विद्यार्थियों को खेती-किसानी और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में एक अभिनव पहल की गई। मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के सहयोग से विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को काली मिर्च एवं सिंदूरी तथा गिलोय आदि पौधों का निशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण,पौधरोपण, व्यावसायिक कृषि तथा बस्तर की अनमोल व विलुप्त हो रही जड़ी बूटियों के संरक्षण संवर्धन के प्रति रुचि जागृत करना और भविष्य में कृषि तथा व्यावसायिक वृक्षारोपण से स्वरोजगार की संभावनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना था। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को मां दंतेश्वरी हर्बल समूह द्वारा तैयार किए गए काली मिर्च, गिलोय एवं सिंदूरी आदि के पौधे निशुल्क प्रदान किए



गए। मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के निदेशक अनुराग कुमार के द्वारा विद्यार्थियों को इन पौधों को अपने घर अथवा उपयुक्त स्थान पर लगाने की व्यवहारिक तकनीक भी समझाया और इनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर लगभग 25 प्रगतिशील किसानों को भी यह पौधे निशुल्क प्रदान किए गए। इस अवसर पर मां दंतेश्वरी हर्बल समूह के संस्थापक डॉ. राजाराम त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को बस्तर की स्थानीय बोली हल्की में संबोधित करते हुए काली मिर्च

और सिंदूरी को खेती के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन पौधों को किस प्रकार लगाया जाता है, उनकी देखभाल कैसे की जाती है और उचित तरीके से खेती करने पर उनसे फसल प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों को यह भी बताया कि काली मिर्च और सिंदूरी जैसे दीर्घजीवी पौधों से लंबे समय तक आय प्राप्त करने की संभावनाएं रहती हैं। डॉ. त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को समझाया कि खेती को केवल पारंपरिक आजीविका के रूप में देखने के बजाय इसे व्यवस्थित व्यवसाय और उद्यमिता के रूप में भी अपनाना जा सकता है। उन्होंने पौधों की उपयोगिता, कृषि आधारित रोजगार और मूल्य संवर्धन की संभावनाओं के बारे में भी विद्यार्थियों को जानकारी दी। उन्होंने

विद्यार्थियों से कहा कि आज लगाया गया एक पौधा आने वाले वर्षों में परिवार की आय का अतिरिक्त स्रोत बन सकता है। इस प्रकार पौधरोपण के साथ-साथ बच्चों में आर्थिक आत्मनिर्भरता की सोच भी विकसित की जा सकती है। विद्यालय के प्राचार्य जमील खान ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को शिक्षा के उद्देश्य और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई-लिखाई का लक्ष्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बने। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि खेती-किसानी को छोटा या सामान्य काम समझने की जरूरत नहीं है। आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक सोच और बाजार की समझ के साथ कृषि को एक सफल व्यवसाय बनाया जा सकता है।

तेंदुपत्ता मजदूरों की मजदूरी बकाया, 12 लाख रुपये लंबित

कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर के भानुप्रतापपुर वनमंडल क्षेत्र में तेंदुपत्ता संग्रहण से जुड़े मजदूरों के लंबित भुगतान का मामला गरमा गया है। करीब एक साल से भुगतान नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने मंगलवार को पूर्व एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने वन विभाग से उनकी मेहनत की बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की। मजदूर संघ के अध्यक्ष सुजीत चक्रधारी ने मीडिया से बात की और अपनी परेशानी बयां की है। उन्होंने बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य से जुड़े मजदूरों का करीब 12 लाख रुपये का भुगतान लगभग एक साल से लंबित है। मजदूरों का आरोप है कि भुगतान



को लेकर कई बार वनमंडल के अधिकारियों से शिकायत और आग्रह किया गया, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। उनकी मांगों को किसी ने नहीं सुना। पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के वनमंडल अधिकारी संदीप बलगा ने इस पर मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि भुगतान स्वीकृत

होने के बाद मजदूरों को उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। वन विभाग पर मजदूर काफी अरसे से आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मजदूरी भुगतान का सिर्फ आश्वासन मिलता रहा है। एक बार फिर आश्वासन मिला है। अब देखना होगा कि तेंदुपत्ता मजदूरी का भुगतान कब होता है।

संक्षिप्त समाचार

महानदी जल विवाद: अमित शाह करेंगे साय और माझी के साथ उच्चस्तरीय बैठक



लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच बातचीत अब महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की उच्चस्तरीय बैठक होने की संभावना है। इसकी जानकारी ओडिशा के महाधिवक्ता पितांबर आचार्य ने दी है। इसी बीच विधानसभा का मौजूदा सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के रायपुर आने और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात करने की भी संभावना है। बता दें कि इससे पहले 20 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की थी। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच छत्तीसगढ़ और ओडिशा के आपसी सहयोग, विकास, जनकल्याण सहित दोनों राज्यों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सौहार्दपूर्ण और सार्थक चर्चा हुई थी। सीएम साय ने महानदी जल विवाद के संबंध में कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस विषय के समाधान की दिशा में अब सकारात्मक वातावरण बना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। केंद्र सरकार के सहयोग और दोनों राज्यों की सकारात्मक पहल से इस विषय का बहुत जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है।

मेयर इन काउंसिल की बैठक आज

रायपुर। रायपुर में श्रीगणेश विसर्जन चल झांकी भारी बारिश के कारण प्रशासन द्वारा एक दिन आगे कर दिनांक 28 सितम्बर को रखे जाने पर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे के आदेशानुसार नगर पालिक निगम की मेयर इन काउंसिल एमआईसी की बैठक नगर निगम सचिवालय द्वारा अब एक दिन आगे कर 30 सितम्बर बुधवार को दोपहर 1 बजे रायपुर नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन महात्मा गाँधी सदन के तृतीय तल स्थित सभाकक्ष क्रमांक 405 में आहुत की गयी है। यहां उल्लेखनीय है कि रायपुर नगर निगम के मुख्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी संख्या में श्रीगणेश विसर्जन चल झांकी की प्रशासनिक व्यवस्था में द्यूटी लगायी गयी है और इसमें रायपुर नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधि एमआईसी सदस्य आमजनों के साथ सम्मिलित होते हैं. श्रीगणेश विसर्जन चल झांकी का आयोजन प्रशासन द्वारा रायपुर में एक दिन बढ़ाये जाने पर रायपुर नगर निगम में एमआईसी बैठक अब 29 सितम्बर के स्थान पर 30 सितम्बर को दोपहर 1 बजे महापौर श्रीमती मीनल चौबे के आदेशानुसार आहुत की गयी है।

अविनाश बिल्डर्स के मैग्नेटो मॉल समेत कई ठिकानों पर जीएसटी विभाग का छापा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जीएसटी विभाग ने अविनाश बिल्डर्स के कई ठिकानों पर छापा मारा है। इस कार्रवाई में जीई रोड स्थित मारुति बिजनेस पार्क, मैग्नेटो मॉल समेत कई जगहों पर अधिकारियों की टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों से कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक, टीम को अविनाश बिल्डर्स द्वारा जीएसटी चोरी की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापा मारा गया है। जीएसटी विभाग के 7 अधिकारियों की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची हुई है। मारुति बिजनेस पार्क और मैग्नेटो मॉल के अलावा चौबे कॉलोनी और आमानाका क्षेत्र स्थित रेसिडेंशियल्स में भी छापेमारी की गई है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में दस्तावेज, बोगस बिल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है। जीएसटी विभाग की टीम अलग-अलग ठिकानों पर दस्तावेजों और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। फिलहाल जीएसटी विभाग की कार्रवाई जारी है। छापेमारी पूरी होने के बाद ही जांच में सामने आए तथ्यों और संभावित जीएसटी चोरी की राशि को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

सितंबर माह का खाद्यान्न वितरण अब 15 अक्टूबर तक

रायपुर। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह सितंबर एवं अक्टूबर 2026 के लिए खाद्यान्न का आबंटन जारी कर दिया गया है। माह सितंबर का खाद्यान्न राज्य की उचित मूल्य दुकानों में भंडारित किया जा चुका है तथा राशनकार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही सभी जिलों में जारी है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 सितंबर 2026 तक राज्य के 71 लाख राशनकार्डधारियों को माह सितंबर का 90 प्रतिशत चावल वितरित किया जा चुका है। शेष राशनकार्डधारियों को भी उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का कार्य निरंतर जारी है। माह सितंबर में वर्षा एवं अन्य कारणों से 30 सितंबर तक खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन द्वारा राशनकार्डधारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की अवधि 15 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई है। इससे शेष राशनकार्डधारी निर्धारित अवधि में अपनी उचित मूल्य दुकान से माह सितंबर का खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

राजधानी/छत्तीसगढ़

सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने मिशन मोड में करें काम : साय

मुख्यमंत्री ने की परिवहन विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए प्रदेश में सुरक्षित, सुगम और आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को न्यूनतम करने के लिए सभी संबंधित विभाग मिशन मोड में समन्वित रूप से कार्य करें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली प्रत्येक संभावित जनहानि को रोकना होना चाहिए। इसके लिए दुर्घटना से पहले रोकथाम और दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता एवं उपचार—दोनों स्तरों पर व्यवस्था मजबूत करनी होगी। उन्होंने ‘जिरो फेटेलिटी’ के लक्ष्य की दिशा

में परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और नगरीय निकायों सहित सभी संबंधित विभागों को विस्तृत और परिणामोन्मुखी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास से जुड़ा विषय है। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षित सड़क संरचना, यातायात और दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता जैसे सभी पहलुओं पर एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और ब्लैक स्पॉट की पहचान कर वहां आवश्यक सुधारात्मक एवं सुरक्षात्मक उपाय प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में



राज्य के 23 ब्लैक स्पॉट में सुधार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने इन कार्यों को तेजी से पूरा करने तथा दुर्घटनाओं के कारणों का नियमित विश्लेषण कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना होने के बाद शुरुआती समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। घायल व्यक्ति तक जितनी जल्दी सहायता और चिकित्सा सुविधा पहुंचेगी, जीवन बचाने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। उन्होंने दुर्घटना की सूचना,

एम्बुलेंस की उपलब्धता, नजदीकी अस्पताल तक पहुंच और उपचार की पूरी व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएम-राहत योजना और राहवीर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों तक यह संदेश प्रभावी रूप से पहुंचना चाहिए कि सड़क दुर्घटना देखकर घबराएं नहीं, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की

रायपुर–बिलासपुर को मिली ‘प्रगति–50 ’ में जगह

सीएम साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्वच्छता मित्रों को दी बधाई

रायपुर। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी ‘प्रगति-50’ योजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को शामिल किया गया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया। देश के चुनिंदा 50 शहरों में राज्य के दो शहरों के शामिल होने से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के नगरीय विकास एवं स्वच्छता प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है।

शुभारंभ कार्यक्रम में चयनित राज्यों के नगरीय विकास विभागों, शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सहभागिता की। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू नई दिल्ली से कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव राजनांदगांव से कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री साय और उप मुख्यमंत्री साव ने ‘प्रगति-50’ में शामिल होने पर रायपुर और बिलासपुर नगर निगमों, दोनों शहरों के स्वच्छता मित्रों और शहरवासियों को बधाई दी है। रायपुर की महापौर मीनल चौबे और बिलासपुर की महापौर



पूजा विधानी के साथ दोनों नगर निगमों के आयुक्त भी कार्यक्रम में ऑनलाइन सम्मिलित हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 51वीं ‘प्रगति’ बैठक के निर्देशों पर शुरु की गई यह पहल स्वच्छ भारत मिशन (और नगरीक सुविधाओं को तेज गति से सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। योजना में देश के 50 शहरों को शामिल किया गया है। इन शहरों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष तकनीकी सहयोग, सतत मार्गदर्शन और गहन निगरानी मिलेगी। साथ ही श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों को अपनाने के लिए भी सहयोग दिया जाएगा।

‘प्रगति-50’ के तहत घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे का वैज्ञानिक पृथक्करण एवं प्रसंस्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और टिकाऊ बनाने तथा सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं

व शहरों की साफ-सफाई में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल के अंतर्गत उपयोग किए गए जल के उपचार, पुनः उपयोग और समुचित प्रबंधन को बढ़ावा देने तथा स्वच्छता अभियानों में नागरिकों, संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाने के साथ ही निर्धारित संकेतकों के आधार पर शहरों के प्रदर्शन की निर्यात समीक्षा एवं मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में राज्य सरकार नगरीय निकायों में स्वच्छता, जनसुविधाओं के विस्तार, प्रभावी कचरा प्रबंधन और बेहतर सेवा-प्रदाय के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है। ‘प्रगति-50’ के लिए रायपुर और बिलासपुर का चयन राज्य सरकार की इन कोशिशों का परिणाम है। इसमें दोनों नगर निगमों की सक्रिय भूमिका, स्वच्छता मित्रों की मेहनत और नागरिकों का सहयोग भी शामिल है। ‘प्रगति-50’ के माध्यम से रायपुर और बिलासपुर को राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियां अपनाने का अवसर मिलेगा। दोनों शहरों में स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन तथा नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार किया जाएगा।

मॉल में अब पार्किंग फ्री, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

रायपुर। उपभोक्ताओं से मॉल में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में बड़ा फैसला सामने आया है। अब अबुजा मॉल सहित प्रदेश के सभी मॉल्स में पार्किंग की सुविधा निशुल्क रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिष्ठोप आयोग रायपुर ने अबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की अपील खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के 22 अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखा है। बता दें कि जिला आयोग ने मॉल आने वाले दोपहिया और चार पहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित मानते हुए निशुल्क पार्किंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

इस मामले में हाईकोर्ट अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला स्वयं परिवादी के रूप में पैरवी कर रहे थे। अपील की सुनवाई के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग समेत विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए पार्किंग शुल्क वसूली के खिलाफ तर्क प्रस्तुत किए।

न्यायमूर्ति गौतम चौर्दड़िया (अध्यक्ष) और प्रमोद कुमार वर्मा (सदस्य) की पीठ ने मामले में जिला आयोग के आदेश की पुष्टि की। आदेश के अनुसार, मॉल प्रबंधन अपनी दुकानों से सुरक्षा, बिजली, एस्केलेटर सहित विभिन्न सुविधाओं के



लिए मेंटेनेंस शुल्क प्राप्त करता है। ऐसे में आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से अलग से पार्किंग शुल्क वसूले जाने को आयोग ने अनुचित माना। आयोग ने पार्किंग शुल्क वसूली को अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी के दायरे में माना है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि निजी संपत्ति पर अवैध रूप से फास्टेग के माध्यम से स्वचालित टोल वसूली का मॉल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत राज्य आयोग प्रदेश का सर्वोच्च अपीलीय उपभोक्ता मंच है। इस आदेश ने यह कानूनी सिद्धांत स्थापित कर दिया है कि जो वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भवन निर्माण नियमों के तहत पार्किंग के लिए एफएसआई छूट का लाभ लेते हैं वे जनता से उस जगह का शुल्क नहीं वसूल सकते। यह निर्णय छत्तीसगढ़ के वसूल जिला आयोगों के लिए बाध्यकारी होगा, जिसका अर्थ है कि अब पूरे राज्य में मॉल द्वारा मनमाना पार्किंग शुल्क वसूलना गैरकानूनी ठहराया जा सकेगा।

बीएसपी स्कैप चोरी मामले में सीबीआई की एंट्री

अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी: साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) से लगभग 250 टन लौह स्कैप चोरी के मामले में अब केंद्रीय अचरणी ब्यूरो (सीबीआई) की एंट्री हो चुकी है। जांच की कमान सीबीआई के हाथों में आते ही प्रदेश में सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। एक ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि सीबीआई जांच में मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि कई नेताओं की इसमें संलिप्तता सामने आई है। मामले को लटकाने के लिए सीबीआई को केस सौंपा गया है।

करोड़ों रुपये के बीएसपी स्कैप चोरी मामले में सीबीआई जांच को



लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि काफी दिनों से मामले में जांच जारी है। इसका स्पष्टता से और व्यापक जांच होनी चाहिए। पुलिस अच्छा काम कर रही थी। जांच के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई।

चूंकि लगातार मामले में बड़े स्तर पर जांच कराने की मांग सामने आई थी, अब केस सीबीआई को फॉरवर्ड किया गया है। बीएसपी स्कैप चोरी मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में क्या राज्य की पुलिस जांच नहीं कर सकती थी? यह चोरी काफी बड़ी है, जिसमें संबंधित नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। जांच की पृष्ठाछ के दायरे में क्या सीबीआई उन नेताओं की भी शामिल करेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले को लटकाने के लिए सीबीआई को जांच सौंप दी गई है।

दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार दिलाने में बड़ी मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के समीक्षा करते हुए इसे और विस्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ग्रामीण, वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों को प्राथमिकता से चिन्हित किया जाए, जहां अभी नियमित सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार जैसी आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच का महत्वपूर्ण आधार है। दूरस्थ गांव को बस सेवा से जोड़ने का अर्थ वहां के लोगों के लिए अनेक नए अवसरों के द्वार में खोलना है। शासन का प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति तक भी सुगम, सुरक्षित और सुलभ सार्वजनिक परिवहन सेवा पहुंचे।

ग्रेड-पे पर बने प्रस्ताव को लागू करने की मांग

नर्सिंग ऑफिसर्स एसो. ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग संवर्ग ने ग्रेड पे वेतनमान पर बने प्रस्ताव को लागू कराने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने चेतावनी दी है कि यदि दीपावली से पहले शासन ने ग्रेड पे संबंधी प्रस्ताव को लागू नहीं किया तो 18 नवंबर से प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग संवर्ग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगा।

एसोसिएशन के अनुसार, संगठन लंबे समय से अपनी एक सूत्रीय मांग ग्रेड पे वेतनमान पर बने प्रस्ताव को लागू करने की मांग को लेकर संघर्षरत है। इसी क्रम में 28 सितंबर को कोरवा, अंबिकापुर और महासमुंद मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों के नर्सिंग संवर्ग ने

अस्पताल परिसर में दो घंटे का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। 29 सितंबर को भी दो घंटे प्रदर्शन किया जाएगा।

इससे पहले रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय परिसर में 9, 10 और 11 सितंबर को भी नर्सिंग कर्मचारियों ने दो घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन किया था। संगठन का कहना है कि लगातार विरोध और मांग उठाए जाने के बावजूद शासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। एसोसिएशन ने बताया

न्यायालय नायब तहसीलदार रायपुर व जिला रायपुर (छ.ग.)
// ईशतहार // रा.प्र. क्र./ /अ-21/वर्ष 2025-2026 रायपुर, दिनांक 25/09/2026 ग्राम टिकरापारा प.ह.नं. 70
एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शैल ठाकुर पिता स्व. जे.आर. ठाकुर निवासी लक्ष्मी नगर दावड़ा कॉलोनी टिकरापारा रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय रायपुर के समक्ष आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा ग्राम टिकरापारा प.ह.नं. 70 तहसील व जिला रायपुर में स्थित परिवर्तित भूमि खसरा नंबर 523/1 रकबा 0.0288 हे. में 3175 वर्गफुट भूमि आवेदक के द्वारा धारित किया जाता है। उक्त भूमि का लगान व अन्य समस्त देय राशि रुपये 30,466/- (अक्षरी तीस हजार चार सौ छहसठ रुपये मात्र) का भुगतान आवेदक के द्वारा किया जा चुका है। आवेदक अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। उक्त भूमि को आवेदक के द्वारा सदीप कुमार जैन पिता स्व. तेज करण जैन निवासी बी-01 आन्नपाली सोसायटी समक्ष मॉल के पास पचवड़ी नाका रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) को विक्रय किए जाने हेतु इकरासमा निष्पादित किया गया है। अतः आवेदक के द्वारा उक्त संपत्ति को विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत आवेदन पत्र धारा-165 (6) भू-राजस्व संहिता के तहत पेश किया है। उक्त प्रकरण अनिवार्याय अधिकारी महोदय रायपुर के माध्यम से इस न्यायालय को प्राप्त प्रतिवेदनर्थ प्राप्त हुआ है।
अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो वे नियत सुनवाई दिनांक 14/10/2026 को स्वतः अथवा वैध प्रतिनिधि के माध्यम से सूत्र न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निवृत्त समयावधि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।
ईशतहार आदि दिनांक 25/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।
नायब तहसीलदार रायपुरवृ (छ.ग.)

न्यायालय कलेक्टर, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)					
:- सार्वजनिक सूचना :-					
क्रमांक // भू-अर्ज/भू.अ.प्र.क. 202601112400021/अ/82 वर्ष 2025-26					
एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत ग्राम ओझुका-अकोलखुर्द-पंधी मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु ग्राम- अकोलखुर्द, प.ह.नं. 36, रा.नि.मं. भिलाई, तहसील आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.) के भू-धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण कार्यपालन अभिर्यता, लोक निर्माण उप संभान-4 (आरंग) रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है जो निम्नानुसार है:-					
क्र.	भूमिस्वामी का नाम, पिता/पति का नाम	ख.नं.	कुल रकबा (हे.)	अर्जित रकबा	भूमि का प्रकार/किस्म
1	रामजी साहू पिता दुकालुराम साहू साकिन अकोलखुर्द,तहसील आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)	528/1	1.0664	0.1064	सिंचित
उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति का कोई दावा/आपत्ति हो, तो वह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।					
कलेक्टर रायपुर (छ.ग.)					
जी-262703594/3					

अगर अमेरिका ने 100% का टैरिफ थोपा तो !

अमेश चतुर्वेदी

अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से ‘सैंक्शनिंग रशा एंड ईरान एक्ट’ के पारित होने को लेकर देश में आशंकाओं के बादलों का उठना स्वाभाविक है। आज जिस आर्थिकी और विश्व व्यवस्था को तकरीबन पूरी दुनिया ने अपना रखा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया को लगता है कि अमेरिका के सहयोग के बिना वह एक कदम आगे नहीं रख सकती। वैश्विक आर्थिकी में डालर के वर्चस्व के चलते ज्यादातर देशों को लगता है कि अगर अमेरिका की आंखें टेढ़ी हुई तो उस पर महाविपत्ति आ जाएगी। इसी सोच का ही असर है कि इस अधिनियम के पारित होने के बाद भारत के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की नजर में भारतीय विदेश नीति नाकाम नजर आने लगी है। सैद्धांतिक रूप से भारतीय वामपंथी इकोसिस्टम अमेरिका का हर पल खुला विरोध करता है, लेकिन उसे भी अमेरिकी टैरिफ कानून भारतीय हित के खिलाफ नजर आ रहा है। इन सबके बीच भारत सरकार की प्रतिक्रिया संतुलित और सधी हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपनी 140 करोड़ की आबादी की ऊर्जा सुरक्षा के लिए दृढ़ है। जाहिर है, भारत को झुकाने की सोच रखने वाले ट्रंप प्रशासन को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं रही होगी। ऐसे में अमेरिका के अगले कदम पर निगाह रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। रूस और ईरान से अगर भारत द्वारा तेल खरीदने का बुनियादी लक्ष्य रूस– यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देना या ईरान–इजरायल युद्ध में अमेरिका और इजरायल का विरोध नहीं है। दरअसल भारत मौजूदा माहौल में अपनी भारी–भरकम जनसंख्या के लिए किफायती ऊर्जा सुरक्षा को संरक्षित कर रहा है। इसलिए भारत का न झुकना देश के विपक्षी दलों और अमेरिकी सरकार के लिए हैरतअंगेज भले ही हो, भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है। वैसे जब से ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है, अपने ऊल–जलूल फैसलों के लिए ही वे जाने गए हैं। यह पहला मौका नहीं है कि उन्होंने इस कानून के जरिए भारत को दबाने की कोशिश की है। बीते साल एक अगस्त 2025 से उन्होंने भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था। जिससे उनके ही बाजार में भारतीय वस्तुएं और सामान महंगे होने लगे थे। तब चालाकी दिखाते हुए ट्रंप प्रशासन ने फार्मास्यूटिकल्स को इस टैरिफ से अलग रखा था। इसकी वजह यह है कि भारत से अमेरिका आने वाली दवाएं सस्ती पड़ती हैं। भारतीय रत्न और आभूषणों पर टैरिफ लगाने का बहुत असर नहीं पड़ा था। क्योंकि रत्न और आभूषण स्वभाव से ही महंगे होते हैं और भारतीय वस्तुएं वाले लोगों के लिए इनकी महंगाई मायने नहीं रखती। ठीक वैसे ही, जैसे भारत में महंगा होने के बावजूद सोने की खरीद–बिक्री पर असर नहीं पड़ा है। भारतीय सामान जब बढ़े टैरिफ के चलते अमेरिकी बाजार में महंगे होने लगे तो अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ सवाल उठने लगे। तब तक अमेरिकी प्रशासन को भी समझ आने लगा था कि उसने कैसा कदम उठाया है। इसका असर यह हुआ कि फरवरी 2026 में ट्रंप प्रशासन को टैरिफ में कटौती करनी पड़ी। पश्चिमी एशिया का हालिया संकट अमेरिका की ही देन है। जब से यह संकट बढ़ा है, भारत ने रूस से तेल की खरीददारी बढ़ा दी है। यह भारत की मजबूरी भी है। बीती जुलाई में भारत ने अपने कुल तेल आयात का 51.4 प्रतिशत तेल अकेले रूस से खरीदा था। रूस से तेल खरीद का भारतीय मकसद मौजूदा हालात में अपने लिए किफायती दरों पर तेल हासिल करना है। भारत का यह अधिकार है और मौजूदा हालात में अगर भारत झुकता है तो इसे भारतीय नागरिक शायद ही पसंद करेगा। भारत की तुलना में चीन ना सिर्फ रूस, बल्कि ईरान से भी भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है।

भारतीय दार्शनिक सम्रदाय

9- बौद्ध दार्शनिक सम्रदायों का वास्तविक विभाजन

गताक्त सं आगे...

ऊपर जो दार्शनिक सम्रदाय बताए गए हैं, उन में से पहले दोनों अर्थात् थेरावादी और सर्वास्तिवादी (वैभाषिक) हीनयान मार्ग के अन्तर्गत हैं, परन्तु शेष तीन अर्थात् माध्यमिक, योगाचार तथा दिङ्नाग-सम्रदाय महायान मार्ग के अन्तर्गत हैं, इन में से थेरावादियों का दार्शनिक साहित्य पाली भाषा में है, जिस पर श्रीमती रीज्ज डेविड्स ने बहुत प्रकाश डाला है।

परन्तु सर्वास्त्रि-वादियों का सारा साहित्य संस्कृत में था, और उसके अन्तर्गत वैभाषिक सम्रदाय का दार्शनिक ग्रन्थ अभिधर्मकोष भी संस्कृत में ही है। यह भ्रम बहुत दिन तक प्रचलित रहा कि हीनयान के ग्रन्थ पाली भाषा में, और महायान के संस्कृत भाषा में हैं, परन्तु अब यह स्पष्ट हो चुका है कि सर्वास्तिवादी हीनयान मार्ग के अनुयायी थे और उनके सारे ग्रन्थ संस्कृत भाषा में थे। यह स्पष्ट ही है कि शेष महायान

के अन्तर्गत तीनों दार्शनिक सम्रदायों- माध्यमिक, योगाचार तथा दिङ्नागीय न्याय-वादियों के ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं।

10 जैन और चार्वाक

वैदिक दार्शनिक सम्रदाय के सर्वदर्शन संग्रह आदि ग्रन्थों में बौद्ध-दर्शन के अतिरिक्त दो अन्य अवैदिक दार्शनिक सम्रदायों का वर्णन है, एक जैन और दूसरा चार्वाक।

जैन धर्म भी बौद्ध धर्म के समान वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड के विद्रोह में खड़ा हुआ था और बौद्ध धर्म के समान वह भी अहिंसाप्रधान, वेद और ब्राह्मणों का विरोधी तथा ईश्वर का निषेध करने वाला था, इसी लिए बहुत दिन तक आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों में यह भ्रम फैला रहा कि जैन और बौद्ध धर्म एक ही हैं। परन्तु अब यह भ्रम सर्वथा दूर हो गया है।



क्रमशः...

ज्ञान/मीमांसा

चुनाव आयोग की साख से सरकार की तीसरे साल की चुनौती तक

शेखर गुप्ता

अगर आप वादा करें कि आप गूगल पर नहीं खोजेंगे तो मैं आपसे तीन सवाल पूछूंगा। पहला, मोदी के कार्यकाल में ज्ञानेश कुमार के पहले कितने मुख्य चुनाव आयुक्त हुए? दूसरा, क्या आपको किसी एक का भी नाम याद है? और तीसरा आपको 1950 से अब तक के कितने मुख्य चुनाव आयुक्तों के नाम याद हैं?

पहले सवाल का जवाब है आठ। मोदी के कार्यकाल में 8 मुख्य चुनाव आयुक्त सम्मानजनक ढंग से अपना दायित्व संभालकर विदा हो चुके हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता कहते हैं इस दौरान उनकी पार्टी को 20 चुनावों में हार मिली और 2024 के लोक सभा चुनाव में पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। आपको 1990 के दशक के टीएन शेषन याद होंगे जिन्होंने इस संस्थान को नए मायने दिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस. वाई. कुरैशी को सार्वजनिक बहसों में सक्रियता के लिए और शायद मनोहर सिंह गिल भी याद किया जाता है।

ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि 1993–95 में गिल ने साथी चुनाव आयुक्त जी.बी.जी. कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर शेषन की ‘तानाशाही’ का सफलतापूर्वक सामना किया और तीनों सदस्यों की समानता के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। गिल बाद में मनमोहन सिंह की सरकार सरकार में राज्य मंत्री बने। शेष 22 मुख्य चुनाव आयुक्त चुपचाप सेवानिवृत्त हो गए। उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से अक्षुण्ण रही। इन्होंने इस संस्थान की गरिमा को बढ़ाने का ही काम किया, क्षति नहीं पहुंचाई।

मैं करीब पांच दशकों से चुनाव और राजनीति पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मुझे भी गिनेचुने नाम ही याद हैं। इनमें से कुछ को तो मैं मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले से निजी तौर पर जानता था। जबकि कुछ अन्य से मेरी बाद में पेशेवर मुलाकातें हुईं।

ऐसे जिस पहले व्यक्ति से मैंने बात की थी वे आर. के. त्रिवेदी थे जिन्होंने 18 जून 1982 से 31 दिसंबर 1985 तक पद संभाला। यह बातचीत उस चुनाव के संदर्भ में हुई थी जिसे इंदिरा गांधी ने असम में उस समय करवाया था जब हिंसक जनबहिष्कार का दौर चल रहा था जिसमें करीब 7,000 लोगों की जान चली गई थी। मैंने त्रिवेदी से पूछा कि उन्होंने इस तरह चुनाव क्यों करवा दिया जबकि उसका व्यापक विरोध हो रहा था। उनका संक्षिप्त जवाब था, ‘मुझे व्यावहारिक होना



पड़ता है।’ बाद में उनका यह वाक्य खूब उद्धृत किया गया।

75 साल पुराना यह संदर्भ इस तथ्य को सामने रखने के लिए है कि ज्ञानेश कुमार अब हमारे 26 मुख्य निर्वाचन आयुक्तों में दूसरे सबसे अविस्मरणीय व्यंक्ति बन गए हैं। जाहिर है उन्होंने यह ‘प्रसिद्धि’ पाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब वे इससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। न ही मोदी सरकार उनसे खुद को अलग कर सकती है। हालांकि संकेत यही हैं कि सरकार ऐसा करना चाहेगी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई प्रभावशाली टिप्पणीकार उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। इनमें चर्चित टीवी एंकर रजत शर्मा भी शामिल हैं जिन्हें कोई भी विपक्ष का भोंपू नहीं कहेगा।

ज्ञानेश कुमार का पद देश के सबसे अधिक संवैधानिक संरक्षण प्राप्त पदों में से एक है। उन्हें कोई बर्खास्त नहीं कर सकता। 2023 के नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किए गए किसी भी कार्य के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। विपक्ष धमकी दे सकता है लेकिन महाभियोग के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है। अगर सरकार उन्हें ‘राजी करके’ पद छोड़ने के लिए कहती है तो इसके राजनीतिक परिणाम गंभीर होंगे। खासकर ऐसे में जब 2029 की गर्मियों में होने वाले बड़े चुनाव तक कई चुनाव होने हैं। वे 26 जनवरी 2029 को अपना कार्यकाल पूरा होने तक पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन तब ये 27 महीने बहुत लंबे साबित होंगे।

मोदी सरकार के लिए यह स्थिति ऐसे समय आई है जो भारत में आमतौर पर सरकारों के लिए मुश्किल माना जाता है यानी कार्यकाल का तीसरा वर्ष। जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी के दौर की शुरुआत से पिछले 60 वर्षों पर नजर डालें तो लगभग हर सरकार ने अपने तीसरे वर्ष के आसपास थकान के संकेत दिखाए और अपनी दिशा से भटकना शुरू किया। केवल वही सरकारें इस संकट से निकल पाईं जिन्होंने अपनी राजनीति या शासन के तौर–तरिकों में नया बदलाव किया।

माधवराव सिंधिया ने जनसंघ से शुरु किया था सियासी सफर

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 30 सितंबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे माधवराव सिंधिया का निधन हो गया था। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर जनसंघ से शुरू किया था। उन्होंने लगातार 9 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वहीं माधवराव सिंधिया केंद्र में नागरिक विमानन, रेल, पर्यटन और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। करीब 4 दशक की राजनीतिक सफर में माधवराव सिंधिया के पास दो ऐसे मौके आए, जब वह मध्यप्रदेश के सीएम पद के करीब पहुंच गए, लेकिन दोनों ही बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया।

मुंबई में 10 मार्च 1945 को माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ था। इनके पिता का



नाम जीवाजीराव सिंधिया और मां का नाम विजया राजे सिंधिया था। पिता की मृत्यु के बाद माधवराव सिंधिया ग्वालियर के महाराज बने थे। इस राजघराने का अपना सिंधिया के पास दो ऐसे मौके आए, जब वह मध्यप्रदेश के सीएम पद के करीब पहुंच गए, लेकिन दोनों ही बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया।

मुंबई में 10 मार्च 1945 को माधवराव सिंधिया का जन्म हुआ था। इनके पिता का

देश के सबसे युवा सांसद बने। इस दौरान बीजेपी के नेता और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन माधवराव सिंधिया अधिक समय तक जनसंघ में नहीं टिके और उन्होंने अपनी मां विजया राजे सिंधिया से बगावत कर कांग्रेस का दामन थाम लिया।

फिर साल 1980 में माधवराव सिंधिया ने गुना से चुनाव जीता और साल 1984 के चुनाव में मां से सीधी टक्कर ने बचने के लिए सिंधिया ने ग्वालियर से चुनाव लड़ा। यह चुनाव इतिहास बन गया, क्योंकि यहां से उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को हराया था। इस चुनाव के बाद से माधवराव का राजनीतिक घोड़ा दिल्ली में रफ्तार से दौड़ने लगा। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की

जिम्मेदारी संभाली।

बता दें कि साल 1998 में सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में माधवराव सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि उस दौरान सोनिया गांधी सही तरीके से हिंदी नहीं बोल पाती थीं, तब माधवराव सिंधिया ने संसद के बाहर और पार्टी के मामलों की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से संभाला। सिंधिया को खेल से भी लगाव रहा था और वह 1990–1993 के बीच बीसीसी के अध्यक्ष भी रहे थे। माधवराव सिंधिया की लोकप्रियता जितनी कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, उतनी की पार्टी से बाहर भी थी।

वहीं 30 सितंबर 2001 को प्लेन क्रैश में माधवराव सिंधिया की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि यदि माधवराव सिंधिया जीवित होते तो मनमोहन सिंह की जगह वह प्रधानमंत्री बनते।

आज का इतिहास

- 1687 औरंगजेब ने हैदराबाद के गोलकुंडा के किले पर कब्जा किया।
- 1870 फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक ज्यॉं पेरिन का जन्म। उन्हें 1926 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- 1947 पाकिस्तान और यमन संयुक्त राष्ट्रसंघ में शामिल हुए।
- 1984 उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच 1945 के बाद पहली बार सीमाएँ खोली गईं।
- 1993 भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में भूकम्प के कारण 10,000 हजार से अधिक लोग मारे गए एवं लाखों बेघर हो गए।
- 1994 अंतरिक्ष शटल एन्डेवर छह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 11 दिन के अभियान पर रवाना।
- 1996 तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया।
- 1996 श्रीलंका की सेना ने तमिल छापामारों के एक गढ़ पर कब्जा किया। आठ दिन के संघर्ष में 900 लोगों की मौत।
- 2001 इस्लामल की आंतरिक मंत्रिपरिषद ने फ़िलिस्तीन के साथ हुए समझौते को मंजूरी दी।
- 2001 कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव राव सिंधिया का निधन।
- 2002 पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुसलमानों ने एक मंदिर को तोड़ा, चीन ने भारत के साथ स्वेच्छा वार्ता को और सार्थक बनाने की इच्छा व्यक्त की।
- 2003 विश्वनाथन आनंद ने विश्व रैंपिड शतरंज चैम्पियनशिप जीती।
- 2004 चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस की 2555वीं जयंती मनाई गयी।
- 2005 समाचार एजेंसी रायटर ने इराक में अमेरिकी सैन्य द्वारा पत्रकारों का दमन करने का आरोप लगाया।
- 2007 परवेज मुशर्रफ़ को दुबारा वर्दी में राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए विपक्ष के 236 सांसदों-विधायकों ने त्यागपत्र दिया। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गांबरी ने विपक्षी नेता आंग सान सूकी और म्यांमार की सैनिक सरकार से मुलाकात की। पाॅप स्टार शकीरा ने पेरू और निकारागुआ में भूकम्प से हुए तबाही के लिए 159.1 करोड़ रुपये दान देने की घोषणा की।
- 2009 प्रख्यात पार्श्व गायक मना डे को वर्ष 2007 प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया।
- 2010 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने विवादित बाबरी मस्जिद मामले में जमीन को तीन हिस्सों में बांटकर रामलला, निर्माँही अखाड़े और वक्फ बोर्ड को एक-एक हिस्सा देने का फैसला सुनाया।
- 2020 बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सभी 32 अभियुक्तों को बरी किया।

ग्लोबल मिशन पर दिसम्बर में निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नीरज कुमार दुबे

भारत की कूटनीतिक गतिविधियां दिसंबर महीने में एक बड़े रणनीतिक अभियान का रूप लेने जा रही हैं और अब पूरी दुनिया मोदी की कूटनीति का कमाल देखने वाली है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित बहु-देशीय यात्रा में अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कम से कम दो देशों को शामिल किए जाने की तैयारी की खबर है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने अभी यात्रा कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत दिसंबर को केवल राजनयिक यात्राओं का महीना नहीं, बल्कि व्यापारिक समझौतों, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शक्ति-संतुलन को साधने के अवसर के रूप में देख रहा है।

मोदी के इस कूटनीतिक अभियान का सबसे बड़ा पड़ाव अमेरिका हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के 14-15 दिसंबर को मियामी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने की संभावना है। यदि यह यात्रा होती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय मुलाकात का भी रास्ता खुल सकता है। इसी मंच पर चार देशों के समूह क्रॉड की संभावित बैठक भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी।

देखा जाये तो भारत-अमेरिका संबंधों में इस समय व्यापार और रूस से जुड़े मुद्दे सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर लगभग सहमत बन चुकी

है, लेकिन इसे लागू करने से पहले भारत अपने निर्यातकों के हित और उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को सुनिश्चित करना चाहता है। साफ है कि मोदी सरकार सिर्फ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि वह ऐसा करार चाहती है जिसका सीधा और ठोस फायदा भारतीय उद्योग और निर्यातकों को मिले।

यहीं से भारत की कूटनीति का दूसरा और अधिक कठिन पक्ष सामने आता है। अमेरिका ने रूस और ईरान से जुड़े नए प्रतिबंध कानून के जरिए रूस की ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाने की संभावना का रास्ता खोला है। इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा रणनीति पर पड़ सकता है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बातचीत में भारत की आर्थिक और रणनीतिक चिंताओं को रखा। अमेरिका की ओर से भी यह संकेत दिया गया कि ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर साझेदार देशों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

यहां भारत की नीति को समझना जरूरी है। नई दिल्ली न तो रूस से संबंध तोड़ रही है और न ही अमेरिका से दूरी बना रही है। सितंबर में मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात में ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हुई। मोदी ने रूस के सामने भी युद्ध को समाप्त करने और संवाद व कूटनीति के रास्ते आगे बढ़ने की बात रखी। इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री की यूक्रेन यात्रा ने यह संदेश दिया कि भारत केवल एक पक्ष से बात करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि अलग-अलग शक्ति



केंद्रों से संवाद बनाए रखने वाला देश है।

यही इस वर्ष की भारतीय कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यूक्रेन युद्ध जारी है, पश्चिम एशिया में संघर्ष और ऊर्जा आपूर्ति पर संकट की आशंका बनी हुई है, अमेरिका-रूस तनाव गहरा रहा है और चीन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। ऐसे वातावरण में भारत ने रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार तथा रणनीतिक सहयोग बढ़ाया, यूरोप के साथ आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी मजबूत की और यूक्रेन के साथ शांति संबंधी संवाद जारी रखा।

उधर, यूरोप के मोर्चे पर भारत को बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है। भारत और यूरोपीय संघ ने 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पूरी की।

सितंबर में यूरोपीय आयोग ने समझौते को हस्ताक्षर और अनुमोदन के लिए परिषद के समक्ष पेश कर दिया। प्रस्तावित समझौते के तहत यूरोपीय संघ के भारत को होने वाले 96 प्रतिशत से अधिक माल निर्यात पर शुल्क घटाने या समाप्त करने की व्यवस्था है। इसलिए दिसंबर में ब्रसेल्स में औपचारिक हस्ताक्षर की संभावना केवल व्यापारिक घटना नहीं होगी; यह भारत-यूरोप संबंधों के व्यापक रणनीतिक विस्तार का प्रतीक भी बन

सकती है।

कनाडा भी इसी कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मार्च 2026 में मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया था। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब कनाडाई डॉलर तक ले जाने की महत्वाकांक्षा भी जताई है। कार्नी ने जून में मोदी के साथ मुलाकात के दौरान संबंधों में सकारात्मक गति और आपूर्ति शृंखलाओं, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया था।

यदि दिसंबर में कनाडा और ब्रसेल्स के पड़ाव जुड़ते हैं तो भारत एक ही यात्रा में उत्तर अमेरिका और यूरोप के दो महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों से संबंधों को नई दिशा दे सकता है। जर्मनी में अंतर-सरकारी परामर्श की

संभावित बैठक इस कूटनीतिक अभियान को और व्यापक बना सकती है।

देखा जाये तो इस पूरी रणनीति का सामरिक अर्थ केवल इतना नहीं है कि भारत नए बाजार खोल रहा है। असली लक्ष्य आपूर्ति शृंखलाओं का विविधीकरण, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और किसी एक शक्ति-केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता से बचाव है। भारत-यूरोपीय संघ के बीच जनवरी में हुए समझौते के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी आगे बढ़ी है, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद-रोधी सहयोग शामिल हैं।

इसलिए भारतीय कूटनीति को केवल यात्राओं और बैठकों की सूची के रूप में देखना अधूरा होगा। इसके केंद्र में एक ऐसी रणनीति दिखाई देती है जिसमें वॉशिंगटन से व्यापार, मॉस्को से ऊर्जा और रणनीतिक संबंध, यूरोप से बाजार और प्रौद्योगिकी, कनाडा से संसाधन व व्यापार और यूक्रेन से शांति संवाद—सभी को एक साथ साधने की कोशिश है।

बहरहाल, भारत का संदेश स्पष्ट है। बदलती विश्व व्यवस्था में नई दिल्ली किसी एक खेमे की परिधि में नहीं, बल्कि अपने आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा हितों के आधार पर अनेक शक्ति केंद्रों के साथ समानांतर संवाद बनाए रखना चाहती है। यही वह संतुलन है जिसने 2026 में तमाम संघर्षों और व्यापारिक तनावों के बीच भारत को वैश्विक कूटनीति के महत्वपूर्ण संवाद केंद्रों में बनाए रखा है।

‘मैं तीन दशकों से मतदान कर रहा हूं, मेरा एसआईआर अधूरा क्यों?’

सुरजीत एस. भट्टा

मैं नई दिल्ली की एक संभ्रांत कॉलोनी में रहता हूं। मैं राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में 3 दशकों से मतदान करता आ रहा हूं। मेरा रिकॉर्ड चुनाव आयोग के डाटाबेस में मौजूद है और आयोग ने इसे मेरे लिए सही और इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनः प्रस्तुत किया है। फिर भी आयोग मेरे एस.आई.आर. आवेदन को मंजूरी नहीं दे पाया है। यह मेरी दुखद कहानी है और इसका अंत सुखद नहीं है। तो आखिर एक सरल, नियमित प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों हो गई है कि लगातार कोशिशों के बाद भी मैं अपने आवेदन को ‘साफ’ नहीं कर पा रहा हूं? लेकिन रैकिंग! मेरा आवेदन तो साफ है। मेरा नाम नहीं बदला, मेरा पता नहीं बदला, जहां तक मुझे याद है, मैं अभी भी जीवित हूं और मैंने हर अपेक्षित चरण का पालन किया है। मुझे अपने दस्तावेज बुध स्तर के अधिकारी के पास ले जाने के लिए कहा गया। लंबी कतार में काफी देर इंतजार करने के बाद, अधिकारी ने मेरे कागजात देखे, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई और मुझे लगभग 2 सप्ताह बाद वापस आकर दूसरी कतार में लगने के लिए कहा निर्धारित दिन दोपहर को एक स्कूल के बाहर बैठक थी। हम लगभग 30 लोग खड़े थे, बैठने की जगह नहीं थी और हमने एक अधिकारी को वे आवेदन प्रस्तुत किए जिनमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई थी। उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रत्येक फाइल की जांच की और फिर अपने मोबाइल फोन से उसकी तस्वीर खींची। बैठक का उद्देश्य कभी नहीं बताया गया क्योंकि सुधार करने के लिए कुछ था ही नहीं। 90 मिनट बाद मैं उनके पास गया। मैंने कहा-जब पहली समीक्षा में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, तो आपने हमें दूसरी समीक्षा के लिए क्यों बुलाया? मेरा आवेदन अधूरा था। किस मामले में अधूरा था? ई.सी.आई. और वे इसका जवाब नहीं दे सके। राज्य द्वारा मेरे रिकॉर्ड के बारे में तथ्यों का एक साधारण सा गलत बयान। उसने कंधे उचका दिए और मुझे

उस पर तरस आया। वह तो बस एक पुर्जा है, मशीन नहीं। मैंने उससे कहा कि वह मेरे एस.आई.आर. दस्तावेज अपने पास रख सकता है, क्योंकि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मैंने वोट दिया या नहीं। बाहर निकलते हुए मैंने लाइन में खड़े लोगों से जोर से कहा-हम सब भेड़ें हैं जो इसे स्वीकार कर रहे हैं और प्रशासन ही हमारा रखवाला है। हम इसे क्यों सह रहे हैं? मैं बहुत गुस्से में हूं और अब मैं इसे और बदलाश नहीं करूंगा। शायद यही अच्छा है। वैसे भी मुझे पता नहीं होता कि किसे वोट दूं। मतदाता सूची को साफ करने की किसी भी प्रक्रिया में 2 तरह की गलतियां हो सकती हैं। या तो यह किसी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से हटा सकती है या फिर किसी मृत या 2 बार दर्ज किए गए व्यक्ति का नाम सूची में छोड़ सकती है। कोई भी प्रक्रिया इन दोनों से नहीं बच सकती। मुख्य प्रश्न यह है कि आप किस गलती से अधिक डरते हैं और इसलिए सबूत का भार किस पर डाला जाए। किसी वास्तविक नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा देने से उसका वोट निश्चित रूप से छिन जाता है। मतदाता सूची में किसी मृत व्यक्ति का नाम होने से तभी नुकसान होता है जब कोई व्यक्ति मतदान केंद्र पर आकर उसके नाम पर वोट डाल दे और इसके खिलाफ मतदान अधिकारी, अमिट स्याही और मतपत्र मौजूद हैं। इससे कहीं अधिक गंभीर गलती मताधिकार से वंचित करना है। इसलिए यह जिम्मेदारी राज्य की होनी चाहिए-मतदाता का नाम मतदाता सूची में तब तक रखा रहता है जब तक राज्य यह साबित न कर दे कि वह अपना पता बदल चुका है, उसकी मृत्यु हो गई है या उसका नाम 2 बार गिना गया है। एस.आई.आर. ने इस व्यवस्था को पूरी तरह उलट दिया। हर मतदाता को शुरू से एक जनगणना प्रपत्र भरना पड़ता था, मानो पिछले 2 दशकों की मतदाता सूचियां मौजूद ही न हों और जिसका प्रपत्र वापस नहीं आता था, उसे मसीढ़ा सूची से हटा दिया जाता था।

सीएम सैनी का बार-बार पंजाब दौरा- सियासत से आगे संदेश की राजनीति

सौरभ वाघर्षेय

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बार-बार पंजाब दौरा इन दिनों राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में किसी पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री का दूसरे राज्य में जाना असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन जब यात्राओं की आवृत्ति बढ़े, उनके साथ राजनीतिक सभाएं, सामाजिक संपर्क, धार्मिक कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियां जुड़ जाएं, तब स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इन दौरों का व्यापक राजनीतिक संदेश क्या है? आखिर हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में इतनी सक्रियता क्यों दिखा रहे हैं?

सैनी के हालिया पंजाब दौरों को केवल सरकारी अथवा सामाजिक कार्यक्रमों तक सीमित करके देखना शायद पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पटियाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, जगरांव और अन्य क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी के अलग-अलग संदर्भ हैं। कहीं धार्मिक कार्यक्रम है, कहीं जनसभा, कहीं किसान और ग्रामीण प्रतिनिधियों से संवाद तो कहीं भाजपा के संगठनात्मक कार्यक्रम। इन सभी गतिविधियों को एक साथ देखने पर पंजाब में उनकी सक्रियता का एक व्यापक राजनीतिक आयाम दिखाई देता है। सबसे पहला कारण दोनों राज्यों के बीच गहरे सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं। हरियाणा और पंजाब केवल पड़ोसी राज्य नहीं हैं, बल्कि दोनों का इतिहास, कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन, व्यापार और सामाजिक रिश्ते एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसानों से जुड़े प्रश्न, कृषि तकनीक, उद्योग, रोजगार, परिवहन, जल और क्षेत्रीय विकास जैसे विषय दोनों राज्यों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए दोनों राज्यों के बीच संवाद और संपर्क स्वाभाविक आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि उद्देश्य केवल क्षेत्रीय सहयोग है तो राजनीतिक सभाओं और संगठनात्मक कार्यक्रमों की संख्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों दिखाई दे रही है? यही वह बिंदु है जहां सैनी की भूमिका मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रमुख राजनीतिक चेहरे के रूप में एक-दूसरे से जुड़ती हुई नजर आती है।

पंजाब की राजनीति में किसान और ग्रामीण समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ग्रामीण प्रतिनिधियों, किसानों और सामाजिक संगठनों तक पहुंच बनाना किसी



भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण है। सैनी के पंजाब दौरों में इन वर्गों के साथ संवाद का बढ़ना इस बात का संकेत है कि भाजपा राज्य में अपनी राजनीतिक और सामाजिक पहुंच को व्यापक बनाने का प्रयास कर रही है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों का भाजपा के साथ जुड़ना भी इसी संगठनात्मक विस्तार की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है।

पंजाब में सैनी की सक्रियता का एक और महत्वपूर्ण पहलू धार्मिक और सांस्कृतिक संपर्क है। जगरांव स्थित नामकसर जैसे धार्मिक स्थलों पर उनकी मौजूदगी, कीर्तन में सहभागिता और लंगर सेवा में भागीदारी केवल धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन राजनीतिक जीवन में ऐसे सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क जनसंवाद का माध्यम भी बनते हैं। पंजाब की सामाजिक संरचना को देखते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से संवाद का अपना अलग महत्व है।

नशे की समस्या भी पंजाब की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है। इस विषय पर सैनी की सक्रियता को भी इसी व्यापक राजनीतिक संवाद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नशामुक्ति के लिए उपचार, पुनर्वास, खेल, शिक्षा और रोजगार जैसे उपायों की चर्चा केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह युवाओं और परिवारों से जुड़ा सामाजिक प्रश्न भी है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप को तथ्यों और राजनीतिक दावों के बीच अंतर रखते हुए देखना जरूरी है।

सैनी की पंजाब यात्रा का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू यह भी है कि भाजपा पंजाब में अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री की सक्रियता को केवल व्यक्तिगत राजनीतिक कार्यक्रम मानना कठिन है। वे भाजपा के एक

प्रमुख नेता होने के नाते पड़ोसी राज्य में पार्टी के राजनीतिक संवाद को विस्तार देने में भूमिका निभा रहे हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि पंजाब और हरियाणा के बीच मौजूद संवेदनशील मुद्दों को इस राजनीतिक सक्रियता से किस तरह प्रभावित किया जाएगा। पानी, चंडीगढ़, कृषि और किसानों से जुड़े विषय दोनों राज्यों में लंबे समय से राजनीतिक महत्व रखते हैं। इन मुद्दों पर किसी भी नेता का बयान केवल एक सामान्य राजनीतिक वक्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि उसके क्षेत्रीय प्रभाव भी होते हैं। इसलिए सैनी के पंजाब दौरों को केवल भाजपा बयाम अन्य दलों की राजनीति के चरम से देखना भी पर्याप्त नहीं होगा।

इन दौरों का संबंध हरियाणा की राजनीति से भी है। मुख्यमंत्री के रूप में सैनी लगातार जनसंपर्क को राजनीतिक कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना, सामाजिक समूहों के साथ संवाद करना और विभिन्न वर्गों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बढ़ाना आज की राजनीति में महत्वपूर्ण हो चुका है। पंजाब में उनकी सक्रियता इस व्यापक जनसंपर्क शैली का विस्तार भी हो सकती है।

दरअसल, आज की राजनीति केवल चुनाव के समय होने वाली सभाओं तक सीमित नहीं है। राजनीतिक दल वर्षभर संगठन विस्तार, सामाजिक संपर्क और जनमत निर्माण की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। धार्मिक संस्थाएं, किसान संगठन, पंचायत प्रतिनिधि, व्यापारी, युवा और सामाजिक संगठन—सभी राजनीतिक संवाद के महत्वपूर्ण केंद्र बन चुके हैं। ऐसे में पंजाब में सैनी की लगातार मौजूदगी को इसी बदलती राजनीतिक कार्यशैली के संदर्भ में समझना अधिक उचित होगा।

फिर भी किसी भी राजनीतिक सक्रियता का अंतिम मूल्यांकन उसके परिणामों से होता है। यदि लगातार दौरों के माध्यम से हरियाणा और पंजाब के बीच उद्योग, व्यापार, कृषि तकनीक, रोजगार, कौशल विकास और नशामुक्ति जैसे साझा मुद्दों पर वास्तविक सहयोग बढ़ता है, तो इसका लाभ दोनों राज्यों के लोगों को मिल सकता है। लेकिन यदि यह सक्रियता केवल राजनीतिक सभाओं, आरोप-प्रत्यारोप और संगठनात्मक विस्तार तक सीमित रहती है, तो इसका अर्थ मुख्यतः चुनावी राजनीति और जनसंपर्क तक सीमित माना जाएगा।

उल्टा दांव?, पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना डिफेंस पैक्ट

विकास मिश्रा

ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही है। वह जो भी कदम उठाता है, वही उल्टा पड़ जाता है। सऊदी अरब और तुर्किये के साथ उसने जो डिफेंस पैक्ट किया था, वह उसके लिए गले की हड्डी बन गया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एयर बेस और तेल के ठिकानों पर इसी महीने कई हमले किए। पैक्ट के अनुसार यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो यह तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस हिसाब से हूतियों के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्किये को अपनी सेना उतार देनी चाहिए थी। लेकिन दोनों ही देशों ने चुपपी साध रखी है।

सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ने पैक्ट के नाम पर सऊदी को ठगने की कोशिश की है? लगता तो यही है। सबसे पहले यह जानिए कि ये हूती हैं कौन? यह संगठन यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय से ताछुक रहता है यह सशक्त हथियारबंद समूह है। इसकी स्थापना 1990 के दशक में यमन के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई थी। इसके संस्थापक थे, हुसैन अल हूती और उन्हीं के नाम पर इसे हूती समूह कहा जाता है। माना जाता है कि इस समूह की स्थापना में ईरान की सबसे बड़ी भूमिका रही है। ईरान उसकी मदद करता है। हूती जिन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करता है, वह उसे ईरान से ही मिलता है। हूती कहता भी है कि हमारा और हिजबुल्लाह के साथ वह ईरान का सहयोगी है।

वर्षों से यमन के अधिकांश आबादी वाले हिस्से पर उसका कब्जा है और यमन की सरकार का उन इलाकों पर कोई प्रभाव नहीं है। चूंकि सऊदी अरब हूतियों के खिलाफ यमन की सरकार की मदद कर रहा है इसलिए हूती पूरी तरह से सऊदी अरब के दुश्मन बने हुए हैं। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सऊदी अरब और हूतियों के बीच युद्धविराम हुआ था लेकिन वह ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया।

अभी जब ईरान को अमेरिका ने घेरने की कोशिश की और हमले किए तो ईरान ने हूतियों को हवा दे दी। चूंकि सऊदी अरब अमेरिका का प्रबल सहयोगी है इसलिए



हूतियों ने सऊदी पर हमले शुरू कर दिए। हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं तो सऊदी ने भी हवाई हमले किए हैं। यानी संघर्ष बढ़ रहा है।

यदि ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी रहती है तो इसका मतलब साफ है कि ईरान भी हूतियों को हवा देता रहेगा और सऊदी अरब के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान उसकी मदद के लिए अपने सैनिक भेजेगा? सीधे तौर पर देखें तो जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके अनुसार पाकिस्तान और तुर्किये को अपनी सेना सऊदी अरब की रक्षा के लिए भेजनी चाहिए।

मगर लगता नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा। पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वह अपना फायदा तो उठा लेता है लेकिन सऊदी की कभी मदद नहीं करता है। सऊदी से उसे पैसा चाहिए और इस पैक्ट के लिए भी निश्चय ही कुछ न कुछ फायदा तो उसने उठाया ही होगा। चूंकि उसके पास परमाणु क्षमता है इसलिए वह सऊदी अरब जैसे देशों को ठगने में कामयाब हो जाता है।

उन देशों को लगता है कि पाकिस्तान मदद करेगा लेकिन पाकिस्तान के रग-रग में दगाबाजी भरी हुई है। वह क्या मदद करेगा? इस विषय को लेकर पाकिस्तान के भीतर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं और यह पूछा जाने लगा है कि क्या इस पैक्ट को साइन करके वह फंस गया है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनिर के तौर-तरीकों पर नजर डालनी

होगी।

मुनिर इस कोशिश में हैं कि पाकिस्तान की पूरी सत्ता उनके कब्जे में हो लेकिन उन्हें पता है कि पाकिस्तान की राजनीति पर सऊदी का छिपा प्रभाव हमेशा बना रहता है। यदि सऊदी साथ नहीं देगा तो मुनिर का बने रहना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने बिना सोचे-समझे डिफेंस पैक्ट को स्वीकार कर लिया। मुनिर ने तात्कालिकता देखी, दूरदृष्टि का उनमें अभाव था।

जिस तरह वे अमेरिका और ईरान की जंग में पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाने में असफल साबित हुए हैं, उसी तरह वे इस डिफेंस पैक्ट में भी असफल साबित होने वाले हैं। मान लीजिए कि वे पाकिस्तानी सेना को सऊदी अरब की मदद में उतार देते हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को ईरान के गुस्से का सामना करना पड़ेगा।

पाकिस्तान और ईरान के बीच 900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा रेखा है जो बलूचिस्तान के इलाके में जुड़ी है। यदि ईरान ने थोड़ी भी नजर टेढ़ी कर ली तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। यह बाद पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है। ईरान का रिश्ता पाकिस्तान से आमतौर पर अच्छा रहा है।

लेकिन अगर उसे लगा कि पाकिस्तानी रबैया उसके हितों के खिलाफ जा रहा है तो वह अपने तेवर बदलने से क्यों हिचकेगा? और यह बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है।यही कारण है कि पाकिस्तान ने हूतियों के हमले के बावजूद अभी तक यह नहीं कहा कि उसकी सेना हूतियों के खिलाफ पैदान में उतरेगी। सऊदी अरब के भीतर पाकिस्तान के करीब आठ हजार सैनिक हमेशा रहते हैं।

और कई लड़कू विमान भी वहां हैं। इसलिए यदि पाकिस्तान चाहे तो उसे हूतियों के खिलाफ उतरने में कुछ मिनट ही नहीं लगेंगे लेकिन वह शायद ही ऐसा कर पाए। हकीकत यही है कि यह डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे उससे न निगलते बन रहा है और न ही उगलते। मगर पाकिस्तान बहुत चालाक है। वह रास्ता निकाल ही लेगा!

अमरीकी प्रेस उठा रही है ट्रम्प की दादागिरी के खिलाफ आवाज

बारबरा मैकक्वेडे

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अब तक निश्चित रूप से जान चुके हैं कि व्हाइट हाउस से मीडिया को अचानक प्रतिबंधित करना गैर-कानूनी है। उनके पास क्रेडेंशियल्स रह करने के वैकल्पिक और वैध तरीके भी हैं जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए इतने हानिकारक नहीं होते। लेकिन बेखोफ होकर मनमानी करना शायद वही तरीका है जिससे ट्रम्प अपने प्रतिद्वंद्वियों को दबाकर झुकाते हैं। इस बार, प्रैस पलटवार कर रही है और बाकी देश को यह सिखा रही है कि किसी धौंस जमाने वाले से कैसे निपटा जाता है। सी.एन.एन., एम.एस. नाऊ और पोलिटिको ने ट्रम्प द्वारा दूरस्थ सोशल पर उनके खिलाफ प्रतिबंध की घोषणा किए जाने के बाद सोमवार को ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आखिर वीरवार को प्रैस को व्हाइट हाउस में जाने की अनुमति मिल गई। ट्रम्प ने यह प्रतिबंध उनकी कथित ‘फेक न्यूज की लगातार ‘रिपोर्टिंग’ के परिणामस्वरूप’ लगाया था। अपने मुकद्दमे में, मीडिया संस्थानों का आरोप है कि व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित किया जाना उनके फर्स्ट अमेंड्मेंट के दृष्टिकोण भेदभाव से स्वतंत्रता के अधिकार (और अपने अधिकारों का प्रयोग करने पर बदले की कार्रवाई से सुरक्षा), साथ ही उनके फिफ्थ अमेंड्मेंट की उचित प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन करता है। एक राष्ट्रपति सैद्धांतिक रूप से वैध आधारों पर मीडिया केडेंशियल्स रह कर सकता है, जैसे कि व्हाइट हाउस के भीतर दुर्व्यवहार लेकिन ऐसा करने के लिए निष्पक्ष सूचना और किसी निष्पक्ष मध्यस्थ द्वारा सुनवाई का अवसर देना आवश्यक होगा। सी.एन.एन., एम.एस. नाऊ और पोलिटिको का कहना है कि उनके क्रेडेंशियल्स छीने जाने से पहले उन्हें ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दी गई और उनकी समाचार कवरेज से राष्ट्रपति की हताशा के अलावा सार्वजनिक रूप से किसी दुर्व्यवहार का उल्लेख नहीं

किया गया है। ट्रम्प ने किसी ऐसे विशिष्ट समाचार या दावे का उल्लेख तक नहीं किया, जिसे वह गलत बताते हों। ट्रम्प निश्चित रूप से जानते हैं कि मुकद्दमा कैसे दर्ज किया जाता है। राष्ट्रपति ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ए.बी.सी. न्यूज और सी.बी.एस. न्यूज जैसे समाचार माध्यमों पर मुकद्दमे किए हैं, जिनके मिले-जुले परिणाम रहे हैं। हालांकि, सी.एन.एन., एम.एस. नाऊ और पोलिटिको पर थोपा गया पूर्ण प्रतिबंध प्रैस संस्थानों और उनके पत्रकारों के प्रथम संशोधन अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। ट्रम्प ने इस जोखिम को तब और बढ़ा दिया, जब उन्होंने मुकद्दमे के अनुसार धमकी दी कि ‘इसके बाद ‘अन्य फेक न्यूज मीडिया आऊटलैट्स’ का नंबर आएगा।’ लेकिन सोमवार दोपहर तक, टी.वी. प्रसारण प्रैस के अन्य सदस्यों ने, जिनमें ‘फॉक्स न्यूज’ भी शामिल है, घोषणा कर दी कि वे ट्रम्प के उन कार्यक्रमों को कवर नहीं करेंगे जो कवरेज के लिए निषेधित थे। इससे पता चलता है कि मीडिया के सदस्यों ने यह सोख लिया है कि किसी धौंस जमाने वाले को हराने का तरीका आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि सामूहिक कार्रवाई है। राष्ट्रपति को उस टी.वी. कवरेज से वंचित करके, जिसके वह भूखे हैं, उन्होंने सबसे अचूक हथियार से वार किया है। ट्रम्प को ऐसे ही प्रतिबंधों पर पहले भी अदालतों में हार का सामना करना पड़ा है, जैसे कि उनके पहले कार्यकाल के दौरान सी.एन.एन. के एक रिपोर्टर के प्रैस क्रेडेंशियल को रद्द करने का उनका असफल प्रयास। सूचना युद्ध ‘एक्टिव मेजर्स’ शब्द का अर्थ ऐसी कार्रवाई करना है, जो आपके प्रतिद्वंद्वी को पहले से तय तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाए। ईरान में युद्ध या अमरीकी कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले ट्रम्प की गिरती लोकप्रियता की रेटिंग पर बात करने की बजाय, मीडिया अब निःसंदेह एक लोकातांत्रिक समाज में स्वतंत्र प्रैस के महत्व की ओर मुड़ जाएगा।



नाश्ते में बनाएं राजस्थानी वड़ा गलगल का अचार और पौष्टिक चीला



गलगल का अचार

क्या चाहिए – गलगल- 2 किलो, हरी मिर्च- 250 ग्राम, अदरक- 250 ग्राम, सरसों का तेल- 200 मि.ली, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर- 2 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर- 1 बड़ा चम्मच, हींग- 1/2 छोटा चम्मच, अजवाइन- 2 बड़े चम्मच, मेथी दाना- 1 बड़ा चम्मच, काला नमक- 2 बड़े चम्मच, सादा नमक- 1 बड़ा चम्मच, शक्कर- 200 ग्राम।
ऐसे बनाएं – एक बड़े बर्तन में पानी को तेज आंच पर गर्म करें। उबाल आने पर साबुत गलगल (नींबू) डालकर 3-4 मिनट उबालें। पानी निथारकर गलगल को पोंछकर सुखा लें। इनको एक इंच के टुकड़ों में काट लें और बीज निकाल दें। हरी मिर्च को एक इंच टुकड़ों में काटें। अदरक के भी एक इंच लंबे कतरे करें। पेन में सरसों का तेल मध्यम से तेज आंच पर गर्म करें। जब इसमें से धुआं निकलने लगे तो इसे आंच से हटा दें। तेल को दस मिनट तक ठंडा करें। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, अजवाइन, मेथी दाने, शक्कर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इसमें डालें गलगल, अदरक और हरी मिर्च। अच्छी तरह से मिलाकर जार में भरें। जार को 15-20 दिन के लिए धूप में रखें जब इसका रंग गहरा और नींबू मुलायम न हो जाए। तैयार अचार को पराठों, चीले आदि के साथ परोसें।

राजस्थानी पौष वड़ा

क्या चाहिए – चावली दाल- 1 कप, चना दाल- 1/2 कप, मूंग की धुली दाल- 1/2 कप, मेथी दाने- 2 छोटे चम्मच, साबुत धनिया- 2 छोटे चम्मच, धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला- 1/2 छोटा चम्मच, हींग- 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच, लौंग- 4, काली मिर्च- 5, हरी मिर्च- 3 कटी हुई, अदरक- 1/2 छोटा चम्मच कटी हुई, हरा धनिया- थोड़ा-सा कटा हुआ, नमक- स्वादानुसार, तेल- तलने के लिए।
ऐसे बनाएं – सभी दालों को रातभर अलग-अलग पानी में भिगोकर रखें। फिर इन्हें निथारकर दरदरा पीस लें। दालों को पीसते समय अगर पानी कम लगे तो 1-2 बड़े चम्मच पानी डाल सकते हैं। ज्यादा पानी न डालें क्योंकि इससे घोल पतला हो जाएगा। लौंग, काली मिर्च, मेथी दाने और साबुत धनिया को भी अलग से दरदरा पीस लें। बोल में पीसी हुई दालें, पीसे हुए मसाले समेत सारी सामग्री डालें और अच्छी तरह मिलाएं। कड़ाही में तेल गर्म करें। एक-एक करके घोल के वड़े तेल में डालें। वड़ों को मध्यम आंच पर सुनहरा-भूरा और कुरकुरा होने तक तलें। चाय या हरी चटनी के साथ गर्मागर्म वड़े परोसें।
मेथी पालक चीला
क्या चाहिए – पालक- 1 कप कटी हुई, मेथी- 1/4 कप कटी हुई, हरा धनिया- 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ, पुदीना- 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ, हरी मिर्च- 1 कटी हुई, अदरक- 1/4 छोटा चम्मच कटी हुई, बेसन- 1 कप, लाल मिर्च पाउडर- 1 छोटा चम्मच, नमक- स्वादानुसार, धनिया पाउडर- 1 छोटा चम्मच, अजवाइन- 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर- 1/4 छोटा चम्मच, हींग- 1/4 छोटा चम्मच, तेल- सेंकने के लिए।
ऐसे बनाएं – बोल में बेसन, पालक, मेथी, मसाले समेत सारी सामग्री डालें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल बनाएं। अब गर्म तवे पर तेल लगाएं और घोल से चीला फैलाएं। चीले पर तेल लगाते हुए दोनों तरफ से सेंकें। जब यह सुनहरा हो जाए तो इस पर कौसा हुआ पनीर और पसंदीदा चटनी लगाएं। इसे अचार के साथ भी परोस सकते हैं।

काम को आसान बना देंगे ये स्मार्ट ट्रिक्स

बना सकते हैं। ये थानदार किचन ट्रिक्स आपका काम आसान करने के साथ-साथ खाने का स्वाद भी बढ़ जाएगा।

- बादाम या टमाटर छिलने के लिए पहले उन्हें 5-10 मिनट तक पानी में उबालें। इससे इनके छिलने आसानी से निकल जाएंगे।
- प्याज को काटने और लहसुन को छिलने से पहले उसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इससे प्याज काटते समय आंसू नहीं आएंगे और लहसुन के छिलने भी आराम से उतर जाएंगे।
- सूखे मेवे या ड्राईफ्रूट्स को काटने से पहले 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इससे यह सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इन्हें आसानी से काट सकेंगी।
- मशरूम को कभी भी पानी से न धाएं। क्योंकि यह पानी को सोख लेते हैं और कपाते समय पानी छोड़ देते हैं, जिससे सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। इसकी बजाए आप मशरूम को गीले कपड़े से साफ करें।
- अगर आप पनीर बना रही हैं तो उसमें थोड़ा-सा ऑयल लगा दें। इससे यह बर्तन के साथ चिपकेंगे नहीं।
- शहद की शुद्धता पता लगाने के लिए उसकी कुछ बूंदें कांच की बोतल या गिलास में डालें। अगर शहद तले पर बैठ जाए तो शुद्ध है और अगर वो पानी में भिक्स हो जाए तो मिलावटी है।
- अगर आप बिरयानी या कोई ग्रेवी वाली डिश बना रही हैं तो उसमें दही डालने से पहले अच्छी तरह फेंट लें। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। इसके अलावा सब्जियां उबालने के बाद इसके पानी को दाल बनाने में इस्तेमाल करें। इससे दाल का स्वाद दोगुना हो जाएगा।
- चावल पकाने से पहले उससे अच्छी तरह से धो लें। इससे चावल में मौजूद स्टार्च निकाल जाएगा और चावल पकने के बाद चिपचिपा नहीं होगा। इसके अलावा चावल की खीर बनाते समय बर्तन में पहले थोड़ा-सा पानी डाल दें। इससे दूध बर्तन के तले पर नहीं चिपकेगा।
- फलों को काटने के बाद उसके उपर अच्छी तरह से नींबू छिड़ककर फ्रिज में स्टोर करें। इससे फल पूरा दिन ताजे रहेंगे और इनका रंग भी खराब नहीं होगा।

इन चार वजहों से मशीन वॉश करने के बाद कपड़ों पर नजर आते हैं सफेद दाग



कपड़े किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। अगर हम साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं तो इससे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ता है। यही कारण है कि लोग एक बार पहनने के बाद कपड़ों को मशीन वॉश करना पसंद करते हैं। लेकिन आपने कहीं बार देखा होगा कि जब आप कपड़ों को मशीन वॉश करते हैं तो अक्सर

उनमें सफेद दाग नजर आते हैं। कपड़ों को धोने के बाद भी जब उन पर सफेद धारियां या धब्बे नजर आते हैं तो यकीनन मन में एक निराशा पैदा होती है। ऐसे में कपड़ों को दोबारा धोने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है। लेकिन कपड़ों के पूरे बैच को दोबारा धोना यकीनन काफी समय लेने वाला होता है। हालांकि, क्या आपने कभी इस बात

पर गौर किया है कि मशीन में कपड़े धोने के बाद भी उनमें सफेद दाग क्यों नजर आते हैं। दरअसल, इसके पीछे कई वजहें जिम्मेदार हो सकती हैं।

पाउडर डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना

कपड़ों को धोने के बाद उन पर सफेद दाग नजर आने का एक मुख्य कारण पाउडर डिटर्जेंट का उपयोग है। अक्सर पाउडर डिटर्जेंट मशीन के पानी में उस तरह से घुलता नहीं है जैसा उसे घुलना चाहिए, जिससे कपड़ों पर धारियां पड़ जाती हैं। इसलिए, अगर आप कपड़ों पर नजर आने वाले इस सफेद दाग की समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं तो पाउडर डिटर्जेंट से लिक्विड डिटर्जेंट पर स्विच करने पर विचार करें।

डिटर्जेंट का अधिक इस्तेमाल करना

कपड़ों का धोते समय डिटर्जेंट की मात्रा भी बहुत मायने रखती है। कई बार लोग बेहतर सफाई के चक्कर में जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हालांकि, ऐसा करने से अवशेष रह सकते हैं क्योंकि यह पूरी तरह से घुल नहीं सकता था



घर खरीदना एक बहुत बड़ा निवेश है। ख़ासतौर पर उनके लिए जिनकी आय सीमित है। अधिकांश युवाओं का मासिक वेतन 15 हजार रुपये प्रति माह से शुरू होकर लगभग 3 वर्षों में 25 से 30 हजार रुपये प्रति माह तक पहुंचता है। इसी में कई खर्चें पूरे करने होते हैं जिसके बाद घर का सपना पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। इसी वर्ग को ध्यान में रखकर हम एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे ताकि हर कोई अपने घर का सपना साकार कर सके।

बजट से शुरुआत

सबसे पहले अपना बजट बनाएं। इस बात का प्रयास करें कि प्रारंभ में आप ऐसा घर खरीदें, जो आपके बजट में आता हो। बाद में उसे बेचकर प्राप्त राशि को डाउन पेमेंट की तरह प्रयोग करते हुए बड़े घर के लिए बड़ा लोन लेने पर विचार कर सकते हैं।

क्षेत्र का चयन

आमतौर पर शहर के व्यस्त या विकसित इलाकों में घरों की कीमतें अधिक होती हैं। इसलिए ऐसे इलाकों की खोज करें जहां अभी कीमतें कम हैं, लेकिन अगले 5 वर्षों में बढ़ने की संभावनाएं हैं।

ऋण की पात्रता जांच लें

कोई भी बैंक घर या प्लेट की कीमत का शत-प्रतिशत लोन नहीं देता है। लोन की राशि घर की कीमत के 80 से 90 फीसदी तक हो सकती है। आपके वेतन से होने वाली कटौतियों को भी ध्यान में रखा जाता है। कुल कटौतियां 60 फीसदी से



पर्सनल स्पेस में प्रोफेशनल लाइफ हो रही है हावी तो इन टिप्स को करें फॉलो

शेड्यूल बनाएं

अगर आप वर्क-फॉर्म-होम और हाइब्रिड वर्किंग के तौर पर काम कर रहे हैं तो आपको समय पर लॉग इन करना चाहिए और समय पर ही लॉग आउट करना चाहिए। अगर आपका बॉस आपको रोजाना ओवरटाइम काम करने को कह रहा है तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए।

ब्रेक लें

वर्क-फॉर्म-होम और हाइब्रिड वर्किंग में आपको काम के साथ बीच-बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। आधे घंटे का ब्रेक लेकर आप खुद के काम को कर सकते हैं। इससे आपको खुद के लिए भी समय मिलता रहेगा।

परिवार के लिए समय

कई बार ऑफिस का काम होने के बाद लोग अपने फोन यानी सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते हैं। हालांकि आपको स्क्रीन टाइम कम करने पर ध्यान देना चाहिए। बचा हुआ समय आपको परिवार को देना चाहिए या फिर आप नई चीजों को सीखने के लिए भी समय निकाल सकते हैं।

काउंसलिंग लें

अगर आप इन चीजों को फॉलो करने के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल स्पेस से अलग नहीं रख पा रहे हैं तो आपको काउंसलिंग लेने की जरूरत है। काउंसलिंग की मदद से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल स्पेस में हावी नहीं होने देंगे।

खर्चों और सीमित आय के साथ खरीदें अपने सपनों का घर

ईएमआई से पहले सिप

यदि लोन लेने के लिए आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो कुछ वर्षों के लिए लोन लेने के विचार को स्थगित करें। ईएमआई का तनाव लेने से अच्छा है कि आप हर महीने किसी अच्छे इकटि म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इवेस्टमेंट की योजना बनाएं।

आवास योजना भी एक विकल्प है

यह पता लगाएं कि आपके शहर में विकास प्राधिकरण की एलआईजी और एमआईजी आय वर्ग के लिए क्या कोई आवास योजना है। प्रायः सभी बड़े शहरों में निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिन शहरों और कस्बों में प्राधिकरण नहीं है, वहां हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में पता करना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग स्क्रीम के अंतर्गत भी सस्ते घर बनाए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत बनाए जा रहे घरों की कीमतें काफी फीफायती होती हैं।



यूपी भाजपा ने एमएलसी चुनाव के छह प्रत्याशी घोषित किए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छह और प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने वाराणसी, मेरठ, झांसी, आगरा और गोरखपुर-फैजाबाद समेत छह सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भाजपा ने वाराणसी स्नातक क्षेत्र से केदार नाथ सिंह, मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल, इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से अशोक कुमार राठी, वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक क्षेत्र से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र से ध्रुव त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। विधान परिषद की 11 सीटों के चुनाव में भाजपा की ओर से पहले पांच प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। अब छह और नामों के ऐलान के साथ पार्टी ने सभी 11 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए अधिपूचना जारी हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी और सपा दोनों की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं।

भाजपा ने बिहार में जदयू छोड़ किसी को नहीं दी सीट

पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चार स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पिछले कई दिनों से भाजपा की लिस्ट का लोग इंतजार कर रहे थे। मंगलवार दोपहर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। खास बात यह है कि बिहार विधान परिषद चुनाव में भाजपा ने जदयू के अलावा अपने किसी भी अन्य सहयोगी दलों को एक भी सीट नहीं दिए हैं। आठ सीटों में चार सीट जदयू को दिया और चार पर आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। भाजपा की ओर से जारी सूची के अनुसार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं इसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. एनके यादव को अलावा दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है।

सीईसी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस

नई दिल्ली। मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक का एजेंडा एसआईआर में कथित अनियमितता रहा। कांग्रेस मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। कार्यसमिति की बैठक में इस विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस कार्यसमिति की यह बैठक ऐसे समय हुई है, जब देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद चल रहा है। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए पार्टी की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हो रही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेता शामिल हुए।

ईसी के खिलाफ साथ आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के प्रमुख राज ठाकरे और यूबीटी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग के खिलाफ एक विरोध मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च भायखला से बीएमसी मुख्यालय तक जाएगा। राज ठाकरे ने कहा 4 तरीख खरो ने इस लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खरगे ने लिखा कि कांग्रेस के कंधों पर अंग्रेजी राज की तरह एक बार फिर भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है। जिस तरह अंग्रेजों से लड़कर वोट का हक छीना, उसी तरह आज भी उसी हक को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है।

भाजपा नेता हसिरानी रथ की उम्मीदवारी नहीं होगी रद्द

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट की एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि भाजपा की नंदीग्राम उपचुनाव उम्मीदवार हसीरानी रथ के चुनावी हलफनामे में उनकी उम्र और स्कूल पास करने के साल में गड़बड़ी है। राज्य कांग्रेस का दावा था कि रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा बताई गई थी, जबकि उन्होंने 10वीं कक्षा पास करने का साल 1965 बताया था, जिससे उम्र के हिसाब से अंतर दिखता है। जस्टिस कृष्णा राव ने कोर्ट में कहा कि राज्य कांग्रेस की याचिका खारिज की जाती है। 25 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद जस्टिस राव ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पास इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि उन्हें उम्मीदवारी की जांच के बारे में शिकायत करने का कोई हक नहीं है। यह कहते हुए कि हलफनामे की जांच करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन में रात

अखिलेश यादव की शर्तों पर क्या झुकेगी कांग्रेस?

नईदिल्ली। आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनाव बढ़ गया है। कांग्रेस गठबंधन में बराबर हिस्सेदारी की मांग करते हुए कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि, खबर है कि समाजवादी पार्टी सितर्फ 85 से 90 सीटें देने को तैयार है और उसने कांग्रेस से उम्मीदवारों की लिस्ट और ज़मीनी रिपोर्ट मांगी है। इस विवाद में रायबरेली और अमेठी जैसे पारंपरिक गढ़ों की सीटें भी शामिल हैं। दूसरी ओर सपा भी कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश में है। खबर है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पर ज्यादा दबाव बन सकता है।

कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम के अनुसार, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट-शेयरिंग का समझौता अक्टूबर में तय होने की उम्मीद है। गौतम ने बताया कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन के तहत कांग्रेस कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गौतम ने कहा कि कांग्रेस के पास सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मौजूद हैं। गठबंधन के तहत, कांग्रेस पार्टी को 50 प्रतिशत सीटें मिलनी हैं। कांग्रेस 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी।

अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने यह भी साफ़ किया कि सीटों के बंटवारे का फ़ैसला पहले से



तय बंटवारे के आधार पर नहीं, बल्कि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में जीत की क्षमता के आधार पर किया जाएगा। यादव ने रायबरेली से सपा के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए ये बातें कहीं। रायबरेली, कांग्रेस नेता और गठबंधन सहयोगी राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है। अपनी पीडीए रथ यात्रा के दौरान समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन पार्टियों को सीटें जीतने की संभावना के आधार पर सीटों के बंटवारे पर बातचीत करनी होगी। समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर साफ़ है। अगर गठबंधन में कोई दिक्कत आती है, तो वह सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पहले उन उम्मीदवारों की पहचान करे जिनके जीतने की संभावना है और उन सीटों को भी चिह्नित करे जहां उसका संगठन मजबूत है और वह अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसके बाद ही वह सीटों के बंटवारे पर आगे बातचीत करना चाहती है।

कांग्रेस में जल्दबाजी का माहौल है। पार्टी गठबंधन तो चाहती है, लेकिन वह इसे जल्द से जल्द पक्का करना चाहती है ताकि उसे पता चल सके कि वह कितने उम्मीदवार उतारेगी और किन सीटों पर

चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी सीट-बंटवारे को अंतिम रूप देने की कोई जल्द नहीं दिखा रही है। समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद ही सीट-बंटवारे पर चर्चा करना चाहती है, जबकि कांग्रेस का मानना ​​? है कि सीटों को तय करने में किसी भी तरह की देरी से उसकी मोल-भाव करने की ताकत कमजोर हो जाएगी। पार्टी को डर है कि अगर सीट-बंटवारे की प्रक्रिया में देरी हुई, तो आखिरकार उसे अखिलेश यादव की शर्तों पर गठबंधन में शामिल होना पड़ सकता है।

दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा कर रही हैं। हालांकि, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही यह बात जानती हैं कि उनमें से किसी में भी अकेले सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है। समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में कांग्रेस की संगठनात्मक मौजूदगी न के बराबर है। नतीजतन, दोनों पक्ष और जवाबी दावे कर रहे हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि साथ आए बिना किसी भी पक्ष के लिए ज्यादा प्रगति करना मुश्किल है। गठबंधन की बातचीत शुरू करने से पहले दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी सोदेबाजी की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं।

कांग्रेस और सपा के बीच सहारनपुर, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी और सीतापुर समेत पांच जिलों को लेकर असली झगड़ा है। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार से जुड़ा रहा है। रायबरेली में 6 विधानसभा सीटें हैं। अमेठी में 4 विधानसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी हर हाल में ऊंचाहार,

हरचंदपुर और सेरनी जैसी सीटों पर अपनी दावेदारी बनाए रखना चाहती है। 2022 के चुनाव में अमेठी की अमेठी सदर और गौरीगंज में सपा के उम्मीदवार जीते थे। रायबरेली में ऊंचाहार, हरचंदपुर, सेरनी और बछरावां में सपा के उम्मीदवार जीते थे। 2027 में भी सपा यहां खुद लड़ना चाहती है। वहीं, कांग्रेस का अपना अलग दावा है।

यूपी चुनाव में 150 सीटों की मांग से पहले कांग्रेस देखें ज़मीनी हकीकत

सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने कांग्रेस से आग्रह किया है कि वह चुनाव लड़ने के लिए सीटों की संख्या तय करते समय व्यावहारिक रख अपनाए। 150 सीटों की कांग्रेस की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सुमन ने कहा कि पार्टी को ज़मीनी हकीकत का आकलन करना चाहिए और उन निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उसकी चुनावी मौजूदगी वास्तविक है। कांग्रेस के 150 सीटों के लक्ष्य पर बात करते हुए रामजी लाल सुमन ने कहा कि कांग्रेस को अपनी मांग तय करने से पहले ज़मीनी हालात को समझना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पार्टी को व्यावहारिक रवैया अपनाना चाहिए और उन सीटों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ वह मजबूत मुकाबला कर सकती है और जीत हासिल कर सकती है। उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब दोनों पार्टियां 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में सीटों के बँटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत कर रही हैं। यह मुद्दा गठबंधन की बातचीत का एक अहम हिस्सा बन गया है क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका चाहती है, जबकि सपा ने हर सीट के हिसाब से आकलन और जीतने की संभावना पर जोर दिया है।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में खरगे का आरोप

वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश सीईसी बने मोदी सरकार की कठपुतली

नई दिल्ली। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस ने सरकार के सामने पांच मांगे रखी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खरगे ने लिखा कि कांग्रेस के कंधों पर अंग्रेजी राज की तरह एक बार फिर भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है। जिस तरह अंग्रेजों से लड़कर वोट का हक छीना, उसी तरह आज भी उसी हक को बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने पोस्ट में लिखा, हमारे पुरखों ने जिस मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी थी, उसे मोदी सरकार ने 12 वर्षों में पड़्यंत्रकारी तरीके से खोखला कर दिया है। खरगे ने कहा कि साजिश के तहत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त सरकार की कठपुतली बन गए हैं।

खरगे ने कहा, बाबा साहेब ने कहा था कि किसी अफसर की मर्जी से मतदाताओं का नाम नहीं कटेगा। आज अफसर भाजपा और मोदी सरकार के इशारे पर मनमर्जी से नाम काट रहे हैं। डॉ. आंबेडकर ने मताधिकार को लोकतंत्र की सर्वाधिक मौलिक चीज कहा था, लेकिन आज इसका उलटा हो रहा है। जनता ने जिसे वोट का चौकीदार बनाया, वही वोटों का लुटेरा बन गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना साधते हुए खरगे ने कहा कि जिस मुख्य चुनाव आयुक्त पर उनके अपने साथी भरोसा नहीं कर रहे, उन पर देश कैसे भरोसा कर सकता है? खरगे ने आरोप लगाया कि चुपचाप फॉर्म 6 के नियमों में बदलाव करवा दिया गया, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। नौकरी तो दी नहीं और अब वोट का अधिकार भी छीना चाहते हैं। खरगे ने आगे कहा, कांग्रेस ने इस देश की संस्थाओं को बनाया और उन्हें अधिकार संपन्न बनाया, लेकिन आज वे ही संस्थाएं सत्ता के आगे



सिर झुकाए खड़ी हैं। भाजपा-आरएसएस योजना के तहत ये काम कर रही हैं।

कांग्रेस ने सरकार के सामने पांच मांगें रखी हैं, जो कि निम्न हैं- 1. मतदाता सूची में होने वाले हर बड़े बदलाव का पूरा डेटा सार्वजनिक हो।

2. जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें पूरी सूचना और अपील का अवसर मिले।

3. राजनीतिक दलों को मतदाता सूची और उससे संबंधित आवश्यक डेटा आसान फॉर्मट में समय पर उपलब्ध हो।

4. जहां गंभीर विसंगतियों के प्रमाण सामने आए, वहां स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो।

5. चुनाव प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा और निगरियां में खुद ऐसे पारदर्शिता हो कि किसी पक्ष को यह कहने का अवसर न मिले कि जानकारी छिपाई जा रही है।

खरगे ने अपने पोस्ट में लिखा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के मतदाताओं को यह भरोसा होना चाहिए कि उनका वोट सुरक्षित है। हम इस मुद्दे को किसी चुनाव को जीतने या हारने की लड़ाई के रूप में नहीं देखते। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, सरकारें आती-जाती हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान स्थायी हैं। यही भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद है। हमें हर नागरिक से कहना है कि लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक आम वोटर है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सत्ता में बैठा नेता नहीं।

खेल प्रमुख समाचार

एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता

नागोया। नीरू ढांडा ने एशियाई खेलों की



महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में मंगलवार को इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले कोई भारतीय महिला ट्रैप या स्कीट निशानेबाज एशियाई खेलों में व्यक्तिगत पदक नहीं जीत सकी थी।

हरियाणा की 26 वर्षीय नीरू ने इससे पहले महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वह जुलाई में इटली में हुए शॉटगन विश्व कप में ट्रैप स्पर्धा का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। नीरू ने फाइनल में 28 अंक जुटाए, जो पिछले 24 अंक के एशियाई रिकॉर्ड से बेहतर है।

चीन की सुन युनॉंग ने 26 अंक के साथ रजत पदक जीता, जबकि कुवैत की अब्दुलमलिक हाजर ने 21 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ने कहा, "मैं यह पदक भारतीय सेना के उन जवानों को समर्पित करती हूँ, जो देश की रक्षा के लिए इससे भी बड़ा काम करते हैं। साथ ही इसे दिवंगत राजा रणधीर सिंह को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने 1978 में एशियाई खेलों में भारत के लिए पहला ट्रैप स्वर्ण पदक जीता था।" अपने अब तक के सफर के बारे में उन्होंने कहा, "2018 जकार्ता एशियाई खेलों में ट्रैप स्पर्धा का रजत पदक जीतने वाले मेरे चचेरे भाई लक्ष्य श्योराण ने मुझे ट्रैप निशानेबाजी अपनाने के लिए प्रेरित किया।

मैं बाद में भोपाल स्थित मध्य प्रदेश निशानेबाजी अकादमी चली गई, क्योंकि वहां मुझे निशानेबाजी अभ्यास के लिए बंदूक और कारतूस मुफ्त में मिल रहे थे।" इससे पहले किसी भी भारतीय महिला ट्रैप निशानेबाज ने एशियाई खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक नहीं जीता था। भारत के लिए पुरुष ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में 1978 में रणधीर सिंह ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था।

आर्थिक/वणिज्य/वित्त/

प्रमुख समाचार

गिरावट के बाद संभला बाजार 242 अंक टूटा सेंसेक्स

मुंबई। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के कारण फ़ोल्ड शेयर बाजार मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को गिरावट के साथ बंद हुए। शुक्रवाती कारोबार में आई भारी गिरावट के बाद हालांकि बाजार ने निचले स्तरों से कुछ रिकवरी दिखाई, लेकिन अंततः दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में ही बंद होने में कामयाब रहे। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 242.65 अंक (0.33 प्रतिशत) टूटकर 72,529.07 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 64.05 अंक (0.28 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 22,716.20 के स्तर पर आ गया। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, इस समय वैश्विक व्यापक आर्थिक परिस्थितियां इकटिरी बाजारों के लिए अनुकूल नहीं हैं। सबसे बड़ा दबाव कच्चे तेल की कीमतों से आ रहा है।

यूई का भारत में 25 अरब डॉलर निवेश का प्लान

नई दिल्ली। संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) भारत में आने वाले समय में 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश करने की तैयारी में है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि यू.ए.ई. का लक्ष्य आने वाले वर्षों में भारत में अपने कुल निवेश को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। गोयल ने भारत-यू.ए.ई. उच्च-स्तरीय कार्य बल की 14वीं बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यू.ए.ई. भारत के बंदरगाह, जहाज निर्माण, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष, स्टार्टअप और शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाश रहा है। पीयूष गोयल ने बताया कि इस अतिरिक्त निवेश का कुछ हिस्सा पहले ही भारत आना शुरू भी हो चुका है। गोयल ने आर.बी.एल. बैंक में करीब 3 अरब डॉलर और सम्मान कैपिटल में करीब 1 अरब डॉलर के निवेश का उदाहरण दिया।

गौतम अडानी को बड़ा झटका नेटवर्थ में बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। फ़रेलू शेयर बाजार में सोमवार को भारी बिकवाली देखने को मिली। इसका असर अडानी ग्रुप के शेयरों पर भी पड़ा और ग्रुप की सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। शेयरों में गिरावट के चलते चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में करीब 3.99 अरब डॉलर की कमी आई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, गिरावट के बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति करीब 103 अरब डॉलर रह गई है। इसके साथ ही वह एशिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में एक पायदान नीचे खिसककर दूसरे नंबर पर आ गए हैं। टिकटॉक के संस्थापक झांग यिमिंग की नेटवर्थ करीब 105 अरब डॉलर बताई गई है। इसके साथ वह एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वैश्विक स्तर पर गौतम अडानी 20वें स्थान पर हैं। हालांकि, साल की शुरुआत से उनकी संपत्ति में अभी भी करीब 18.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है।

सेबी का 192 करोड़ की निवेश योजना बंद करने का आदेश

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने ऑनलाइन कृषि निवेश मंच ग्रोपिटल से जुड़ी करीब 192.88 करोड़ रुपए की निवेश योजना को बंद करने का आदेश दिया है। सेबी के अनुसार, इस योजना के जरिए 5,208 निवेशकों से रकम जुटाई गई थी। नियामक ने इसे अनधिकृत सामूहिक निवेश योजना माना है। ग्रोपिटल को शुरुआत 2020 में हुई थी। मंच पर निवेश की शुरुआत करीब 5,000 रुपए से की जा सकती थी। निवेशकों से जुटाई गई रकम को कृषि परियोजनाओं में लगाने का दावा किया गया था। सेबी के मुताबिक, निवेशकों को इकाइयों के बदले मुताफे या रिटर्न का भरोसा दिया गया था। योजना में सुनिश्चित और टैक्स-फ्री रिटर्न का भी वादा किए जाने की बात सामने आई है।

टेलीकॉम कंपनियों पर लगी लगाम– उपभोक्ता हित में जरूरी नियमन

सौरभ वार्णाय

देश की अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मोबाइल फोन और इंटरनेट संचार के साधन भर नहीं रह गए हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार, रोजगार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच की बुनियादी जरूरत बन चुके हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सेवा की गुणवत्ता, शुल्क की पारदर्शिता, स्पैम कॉल, डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता शिकायतों जैसे मुद्दों पर बड़ों नियामकीय सख्ती इसी बदलती जरूरत का संकेत है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को सस्ते डेटा और अनेक सेवाओं का लाभ मिला है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठे हैं। अनचाहे कॉल और संदेश, अस्पष्ट शुल्क, खराब नेटवर्क,

शिकायतों के समाधान में देरी और निजी डेटा की सुरक्षा जैसे मुद्दे लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। जब कोई सेवा करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए, तब केवल व्यावसायिक लाभ पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बाजार की ताकत के साथ उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही भी जरूरी है।

इसी संदर्भ में रिचार्ज की वैधता का सवाल खास महत्व रखता है। मोबाइल सेवा अब ऐसी जरूरत है, जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना संभव नहीं। 28 दिन वाले मासिक रिचार्ज को लेकर मार्च 2026 में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में सवाल उठाया था कि 12 महीनों के वर्ष में 28 दिन की वैधता वाले चक्र से उपभोक्ता को प्रभावी रूप से साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ सकता है। उन्होंने उन उपभोक्ताओं के लिए भी कफायती विकल्पों की जरूरत बताई, जिन्हें मोबाइल डेटा की आवश्यकता



नहीं है। यह बहस अब नियामकीय बदलाव तक पहुंच चुकी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को टेलीकॉम कॉन्ज्युमर्स प्रोटेक्शन अमेंडेंट रेगुलेशंस, 2026 अधिसूचित किए हैं। नए प्रावधानों के तहत कंपनियों को उन वैधता अवधियों को अनुरूप वॉइस और एसएमएस ऑनली स्पेशल टैरिफ वॉउचर्स उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें 30 दिन या उससे कम अवधि वाले डेटा-बंडल प्लान शामिल हैं। इसके अलावा समान तरीख पर हर महीने नवीनीकरण वाला विकल्प और लंबी वैधता वाला कम-से-कम एक वॉइस एसएमएस ऑनली विकल्प भी उपलब्ध कराना होगा।

इन वाउचर में उचित टैरिफ कटौती का भी प्रावधान है।

इस बदलाव का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि हर उपभोक्ता को समान प्रकार की सेवा को जरूरत नहीं होती। बुजुर्ग, फीचर फोन उपयोगकर्ता, सीमित डेटा इस्तेमाल करने वाले या कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा पर्याप्त हो सकती है। यदि उन्हें अनिवार्यक डेटा के साथ बंडल प्लान लेने के लिए मजबूर होना पड़े, तो चॉइस का अर्थ ही कमजोर हो जाता है। नियमन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार भुगतान कर सकें।

हालांकि, 30 दिन का विकल्प उपलब्ध होना अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है। असली सवाल यह होगा कि कंपनियां इन प्लान को कितनी आसानी से उपलब्ध कराती हैं और उनकी कीमत क्या रहती है। यदि

वॉइस एसएमएस ऑनली प्लान केवल नियमों की खानापूर्ति के लिए बनाए जाएं, उनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध न हो या उनकी कीमत डेटा वाले प्लान के मुकाबले पर्याप्त रूप से कम न हो, तो उपभोक्ता को वास्तविक लाभ सीमित रह जाएगा। इसलिए पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी इस व्यवस्था को सफलता की अनिवार्य शर्त हैं।

टेलीकॉम नियमन का दायरा केवल रिचार्ज तक सीमित नहीं है। स्पैम कॉल और अनचाहे व्यावसायिक संदेश भी उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा बड़ा प्रश्न हैं। बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट और अन्य सेवाओं के नाम पर आने वाले लगातार प्रचार संदेश कई बार धोखाधड़ी का माध्यम भी बन जाते हैं। ऐसे में वैध व्यावसायिक संचार और संदिग्ध गतिविधियों के बीच स्पष्ट अंतर करना तथा नियमों का उद्घेष्ट करने वालों पर कार्रवाई करना जरूरी है।

युवा शक्ति, नवाचार और स्टार्टअप्स की भागीदारी से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

युवा केवल नौकरी मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनें : विष्णुदेव

रायपुर। छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति प्रदेश के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के युवा केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं, बल्कि अपने कौशल, नवाचार और उद्यमिता के बल पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाले बनें। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं, नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य सरकार युवाओं के विचारों को नवाचार और नवाचार को सफल उद्यम में बदलने के लिए आवश्यक वातावरण, अधोसंरचना, तकनीकी सहयोग और प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक मंडप में आयोजित तीन दिवसीय ‘युथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026’ में प्रदेशभर से आए विद्यार्थियों, युवा नवाचारकर्ताओं और स्टार्टअप उद्यमियों को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का युवा केवल अवसर की प्रतीक्षा करने वाला युवा नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा से नए अवसर गढ़ने का सामर्थ्य रखता है।



नई औद्योगिक नीति के बाद 8.23 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को अब तक लगभग 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश की यह प्रक्रिया केवल प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनेक परियोजनाओं पर धरातल पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब परंपरागत उद्योगों के साथ-साथ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, टेक्स्टाइल और अन्य उभरते क्षेत्रों में भी निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा, ऊर्जा क्षमता, देश के मध्य में स्थित भौगोलिक स्थिति तथा लगातार मजबूत हो रही सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी निवेश और उद्यमिता के लिए छत्तीसगढ़ की संभावनाओं को और सशक्त बना रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं से कहा कि वे नई औद्योगिक नीति का गंभीरता से अध्ययन करें और उसमें उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठाएं। प्रदेश में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है।

किसान परिवार के अनुभव युवाओं से किए साझा

युवाओं के साथ संवाद के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने कृषक परिवार और गांव बगिया से जुड़े अनुभव भी साझा किए। उन्होंने कहा कि वे किसान परिवार से आते हैं और स्वयं खेती-किसानी, हल चलाने तथा पशुपालन के कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के साथ उसमें छिपी संभावनाओं को भी वे निकटता से समझते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। आधुनिक तकनीक और नवाचार को कृषि से जोड़कर युवाओं के लिए उद्यमिता के व्यापक अवसर तैयार किए जा सकते हैं। कृषि के साथ कृषि जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उभरते क्षेत्रों में युवा अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ को 182 करोड़ की राशि का आवंटन



नई दिल्ली राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में शामिल हुए मंत्री रामविचार नेताम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में शामिल हुए। 28 और 29 सितंबर को आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के कृषि मंत्रियों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं राज्यमंत्री की उपस्थिति में आगामी रबी फसल को लेकर व्यापक कार्ययोजना तैयार करने पर विचार-विमर्श

किया गया।

सम्मेलन में कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के विभिन्न घटकों का प्रभावी क्रियान्वयन करने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ पहुंचाना, कृषि की लागत को कम करना और किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रभावी कदम उठाना है।

उन्होंने बताया कि सम्मेलन के दौरान भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 182 करोड़

रुपए का आवंटन जारी किया गया और इसका पत्र भी प्रदान किया गया। उन्होंने प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि छत्तीसगढ़ में कृषि विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने कहा कि इस राशि से प्रदेश में चलाए जाने वाले 'विकसित संकल्प अभियान' को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही आगामी समय में 'खेत बचाओ अभियान' के माध्यम से किसानों को बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

बस्तर में बारिश और बाढ़ से तबाही मुख्यमंत्री का दौरा केवल खानापूति : दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बस्तर संभाग का अधिकांश हिस्सा बारिश और बाढ़ के कारण तबाह हो चुका है। बस्तर संभाग के 571 गांवों में बाढ़ से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। 22 हजार से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आये हैं। 8 लोगों की मौतें भी हुई हैं। लोगों के घर, घर के सामान राशन सामग्री, काँपी-किताब, दस्तावेज सब बर्बाद हो गया है। इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सरकार के द्वारा जिस मुस्तेदी से राहत और बचाव कार्य किया जाना चाहिए वह नहीं दिखा। मुख्यमंत्री कल



बस्तरवासियों को उम्मीद थी की कुछ ठोस घोषणा करेंगे लेकिन उन्होंने निराश किया। हमारी मांग है सरकार बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता और क्षेत्र के पुल-पुलिया, सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज दें। पिछले वर्ष भी बारिश की तबाही से बस्तर के अनेकों पुल-पुलिया टूट गये थे, सड़कें बह गयी थी, वे अभी तक नहीं बनी हैं।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री साय, हर साल बाढ़ में बस्तर सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं फिर पीड़ितों को उनके हाल में छोड़कर भूल जाते हैं, पिछले साल के आपदा राहत के अधूरे काम कब पूरे करेंगे? 2025 की बाढ़ में सड़कें, पुल-पुलिया क्षतिग्रस्त हुए थे, तब जल्द मरम्मत और पुनर्निर्माण का भरोसा दिया गया था।

ग्रामीणों ने निकाली जल संरक्षण जागरूकता रैली

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के मस्तुरी विकासखण्ड के ग्राम करी में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) एवं पंचायत विभाग के संयुक्त समन्वय से आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों को जल स्रोतों के संरक्षण, जल के समुचित उपयोग तथा वर्षा जल के संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से जल संरक्षण को लेकर संवाद किया गया।

सीआईआई एमएसएमई कॉन्क्लेव 2.0 का उप मुख्यमंत्री शर्मा व उद्योग मंत्री ने किया शुभारंभ

रायपुर। राजधानी रायपुर में भारतीय उद्योग परिषद (सीआईआई) छत्तीसगढ़ राज्य परिषद द्वारा आयोजित दो दिवसीय एमएसएमई कॉन्क्लेव 2.0 का सोमवार को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा और उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने शुभारंभ किया। नवाचार एवं सतत औद्योगिक विकास द्वारा एमएसएमई का सशक्तिकरण विषय पर आयोजित कॉन्क्लेव के पहले दिन 250 से अधिक उद्यमियों, नीति-निर्माताओं और



उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वित्तपोषण, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों

पर विस्तार से चर्चा हुई। कॉन्क्लेव का उद्घाटन सत्र में उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और आर्थिक विकास में छोटे उद्योगों, कारखानों और कार्यशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। एमएसएमई के विकास से लिए बेहतर कानून-व्यवस्था, सुरित सड़क संपर्क और त्वरित स्वीकृतियां आवश्यक हैं। राज्य सरकार इन तीनों क्षेत्रों में बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

बाढ़ के बीच घर-घर पहुंची राहत की मदद

सुकमा। लगातार बारिश और जलभराव से प्रभावित परिवारों के बीच राहत और भरोसे का संदेश लेकर जिला प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों की टीम मंगलवार को सुकमा नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में पहुंची। एसडीएम श्री सूरज कश्यप, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुमित ध्रुव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री विनीत साव सहित अधिकारियों-कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने पुसामी पारा, सुपनार, वार्ड क्रमांक 6, श्रीनगर वार्ड क्रमांक 6 तथा वार्ड क्रमांक 11, 12 एवं 13 का भ्रमण कर प्रभावित परिवारों से सीधे मुलाकात की। मुश्किल की घड़ी में जब प्रशासन घर की चौखट तक पहुंचा, तो प्रभावित परिवारों को जरूरी राहत के साथ संबल भी मिला। अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने परिवारों से उनकी स्थिति और समस्याओं की जानकारी ली तथा उनकी जरूरतों को समझते हुए सूखा राशन, शॉल, चादर, प्लेट एवं गिलास सहित आवश्यक राहत सामग्री वितरित की।

दो माह का एकमुश्त चावल देने की घोषणा हवा हवाई : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर गरीबों के राशन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सितंबर और अक्टूबर का दो माह का चावल एकमुश्त देने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो कर दीं, लेकिन जमीनी स्तर पर राशन वितरण की व्यवस्था ही चरमरा गई। सितंबर खत्म होने में चंद दिन शेष हैं और प्रदेश में 25 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को सितंबर का चावल तक नहीं मिल पाया है। सरकारी पोर्टल पर भी 24 सितंबर तक सितंबर माह में लगभग 57.43 लाख कार्डों पर ही वितरण दर्ज है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार की घोषणा कागज पर दो माह के राशन की है, लेकिन गरीब की राशन दुकान पर पहुंचते ही व्यवस्था का सच सामने आ जाता है। कहीं चावल का स्टॉक नहीं है, कहीं परिवहन की समस्या है और कहीं सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त आवंटन दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा यह है कि गरीब हितग्राही राशन दुकान के चक्कर काटने को मजबूर हैं। रायपुर सहित कई जिलों में दुकानों में चावल नहीं पहुंचने और अतिरिक्त आवंटन सॉफ्टवेयर में नहीं दिखने की शिकायतें सामने आई हैं।

पैरा खिलाड़ी स्वाति को कलेक्टर ने सौंपा 21 हजार का चेक

बिलासपुर। मुख्यमंत्रीविष्णुदेव साय के नेतृत्व में बेटियों को शिक्षा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिले की प्रतिभावान पैरा पैरॉसिंग खिलाड़ी कु. स्वाति साहू को 21 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज अपने कार्यालय में स्वाति को सम्मानित कर प्रोत्साहन राशि का चेक सौंपा और उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। आदर्श चौक, बहतराई निवासी स्वाति साहू ने विपरीत परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए पैरा फेंसिंग में राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 22 पदक, जिनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 15 कांस्य पदक शामिल हैं, अपने नाम किए हैं। इसके अलावा व्हीलचेयर फेंसिंग में एक स्वर्ण तथा कराटे में 6 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। वर्ष 2026 में थाईलैंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय पैरा फेंसिंग प्रतियोगिता में भी उन्होंने सहभागिता की। स्वाति को शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार 2024-25, मुख्यमंत्री खेल अलंकरण 2022-23, निषाद गौरव खेल पुरस्कार 2022-23 एवं तेजस ध्यान खेल पुरस्कार 2025-26 से भी सम्मानित किया जा चुका है।

महंगाई सूचकांक आजादी के बाद सबसे जादा 9.78 पहुंचा : कांग्रेस

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी, घटते इनकम से लोग परेशान हैं वहीं दैनिक उपभोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के चलते ही महंगाई बेलगाम हो चुकी है। 1 डॉलर की कीमत 96 रुपये तक पहुंच गया है। केंद्र की मोदी सरकार आम जनता से डीजल, पेट्रोल का डेढ़ गुना दाम वसूल रही है। रसोई गैस की कीमतें तीन गुना अधिक वसूली जा रही है। दूध, दही, पनीर, आटा, मैदा, सूजी, दलहन तिलहन, कपड़े जैसे दैनिक उपभोग की तमाम वस्तुओं के दाम बढ़ गये हैं। दवाओं और अस्पतालों तक में इलाज महंगा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार जनता की जेब में खुलेआम डकैती कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने बढ़ती महंगाई पर गहरी चिंता व्यक्त किया है। देश का थोक महंगाई सूचकांक आजादी के बाद सबसे ऊंचे पायदान 10(9.78) तक पहुंच गया है। रोजमर्रा की जरूरतों के समानो की बेतहाशा बढ़ी महंगाई तथा खाद्य तेल, शक्कर प्याज के बढ़े दाम आम आदमी को परेशान कर रहे हैं। राशन सामग्री के दाम दुगुने हो गये हैं, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस तथा बड़े बिजली बिल से जनता के घर का बजट बिगड़ गया है।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं

बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने उनसे मिलकर निजी एवं सामुदायिक शिकायत संबंधी आवेदन दिया। उन्होंने अधिकांश मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी एवं अपर कलेक्टर श्री वीरेंद्र बहादुर पंचभार्ई ने भी लोगों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में मस्तुरी तहसील के ग्राम गतौरा निवासी गनेश राम कोसले ने ज्ञापन सौंपकर बंद किसान सम्मान निधि की राशि पुनः शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में उन्हें किसान सम्मान निधि की राशि प्राप्त हो रही थी, लेकिन वर्तमान में सहायता राशि बंद हो गई है। राशि बंद होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार सरकंडा के नत्थूलाल ने भी विगत चार-माह से बंद वृद्धा पेंशन राशि के संबंध में कलेक्टर से मुलाकात की। ग्राम लिमतरा निवासी पार्वती पटेल ने बताया कि उनकी भूमि का कुछ हिस्सा सड़क निर्माण के लिए लिया गया है, जिसके मुआवजे की राशि अभी तक लंबित है।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा 1 से 3 नवम्बर तक आयोजित होगा राज्योत्सव

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्योत्सव एवं राज्य अलंकरण समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को समय-सीमा में तैयारियां पूर्ण करने तथा विभागीय प्रदर्शनी को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने 22 अक्टूबर तक विभागवार तैयारियों एवं प्रदर्शनी की जानकारी उपलब्ध



कराने को कहा। उन्होंने राज्योत्सव को केंद्रीय थीम आधारित स्वरूप में आयोजित करने पर जोर दिया। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव पूंजी विकास, विकसित भारत, अंजोर छत्तीसगढ़ जैसे विषयों के साथ भविष्य की दिशा और विकास पर फोकस रखने के निर्देश दिए। राज्योत्सव के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा 40 राज्य स्तरीय अलंकरण एवं पुरस्कार प्रदान किए

जाएंगे। पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। राज्य स्तरीय आयोजन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर (मेला ग्राउंड) नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम-तृता में प्रस्तावित है। विभागों को दी गई प्रमुख जिम्मेदारियां सीएसआईडीसी, एनआरडीए,

लोक निर्माण विभाग को मेला स्थल का ले-आउट, स्टेल आंबटन, विकास प्रदर्शनी की व्यवस्था, मुख्य मंच, डोम, पंडाल, बैठक एवं बैरिकेटिंग की जिम्मेदारी दी गई है। जनसंपर्क विभाग एवं चिप्स द्वारा प्रचार-प्रसार और हाईटेक मीडिया सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। नगर निगम रायपुर एवं एनआरडीए नागरिक सुविधाओं, सिटी बस, पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था करेंगे।

विश्व हृदय दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के नेतृत्व में निकली मेगा जागरूकता रैली

बड़ी संख्या में नागरिकों ने लिया हिस्सा, स्वस्थ हृदय के लिए दिया जागरूकता का संदेश

बिलासपुर। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर आज स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर एवं अपोलो हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में मेगा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, नगर



निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। विश्व हृदय दिवस की इस वर्ष की थीम 'डॉट मिस ए बिट' के अनुरूप प्रतिभागियों ने लाल रिबन लगाकर हृदय स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया।

रैली सोमपेड़ी चौक से प्रारंभ होकर अरपा रिवर व्यू तक पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर हृदय रोगों के जोखिम को काफी हद

तक कम किया जा सकता है। उन्होंने नियमित व्यायाम, संतुलित खान-पान और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए जागरूकता और अनुशासित जीवनशैली बेहद जरूरी है। रैली के सफल आयोजन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गरेवाल, जिला नोडल अधिकारी डॉ. बी.के. वैष्णव एवं जिला स्वास्थ्य अधिकार डॉ. अनुपम सहित स्वास्थ्य विभाग और अपोलो हॉस्पिटल की टीम का विशेष सहयोग रहा।